राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक
साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

फल्गुन 5, बुधवार, शाके 1942 - फरवरी 24, 2021
Phalguna 5, Wednesday, Saka 1942- February 24, 2021

भाग 4 (ग)
उप-खण्ड (II)
राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी
किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

बित्त विवाह
(कर अनुमान)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 24, 2021

एस.ओ.451.- राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 9) की
धारा 174 की उप-धारा (2क) द्वारा पद्धत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने
पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, कर की रिवेंट और परदेश मांगों और विवादों के
निपटान के लिए निम्नलिखित " zaman स्कीम-2021", जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम के रूप में
निर्देश किया गया है, इसके द्वारा आधिसूचित करती है, अर्थात् :-

1. संस्कृत नाम और प्रवत्तन कालावधि.- (1) इस स्कीम का नाम इमेनेस्टी स्कीम-2021 है।
(2) यह स्कीम तुरंत प्रकृत होगी और 30.09.2021 तक प्रकृत रहेगी।
2. लागू होना.- संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 54 में सम्मिलित
माल के संबंध में परदेश मांगों या विवाद के सिवाय, यह स्कीम ऐसे समस्त व्यवहारियों या
व्यक्तियों पर लागू होगी जिनके विश्वसन 30.06.2017 तक की कालावधि के संबंध में, किसी
अधिनियम के अधीन कोई परदेश मांग या विवाद है।
3. परिभाषाएँ.- (1) इस स्कीम में, जब तक विश्वय या संदेश से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
(क) "अधिनियम" से निम्नलिखित में से कोई अधिनियम अभिप्रेत है :-
(i) राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम सं. 29);
(ii) राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (1995 का अधिनियम सं. 22);
(iii) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 74);
(iv) राजस्थान मूल्य परिवंध कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4);
(v) राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (1999 का
अधिनियम सं. 13);
(vi) राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में मोटर यात्रा के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1988
(1988 का अधिनियम सं. 14);
भाग 4(ग) राजस्थान राज-पत्र, फरवरी 24, 2021 856

(vii) राजस्थान मनोरंजन और विजापन कर अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम सं. 24);
(viii) राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 (1996 का अधिनियम सं. 9); और
(ix) राजस्थान विलासों (तम्भाकू और उसके उत्पाद) पर कर अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 11);
(ख) "स्वीकृत कर" से कोई रक्ष कार्यरत है जो व्यवहारी या व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गई किसी विवरण में या किसी प्राधिकारी के समक्ष लिखित में सूचीकृत की गई है;
(ग) "आवेदक" से कोई व्यवहारी या व्यक्ति कार्यरत है जो स्क्रीम के अधीन फायदे प्राप्त करने की अपनी रजामंदी सूचित करता है;
(घ) "निर्धारण प्राधिकारी" से अधिनियम के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी या प्राधिकारी कार्यरत है;
(ङ) "व्यवहारी" से अधिनियम के अधीन यथाप्रस्तावित कोई व्यवहारी अभियंत है;
(च) "घोषणा प्रस्तुत" से कर की रियायती दर पर माल के क्राग या विक्रय या कर से छूट के लिए अधिनियम के अधीन विहिंड कालिनी प्रस्तुत या प्रमाणपत्र अभियंत है;
(छ) "विभाग" से वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान अभियंत है;
(ज) "अंतर कर" से अधिनियम के अधीन राज्य में लागू कर की पूर्ण दर और रियायती दर या छूट, जो घोषणा प्रस्तुत के प्रस्तुत किये जाने पर माल है, के मध्य अंतर अभियंत है;
(झ) "विवाद" से अधिनियम के अधीन 30.06.2017 तक की किसी कालवधि के संबंध में निम्नलिखित से संबंधित, कोई लंबी मामला अभियंत है:-
(i) अधिनियम के अधीन नियुक्त या विहि त या प्राधिकृत किसी प्राधिकारी द्वारा कर, व्याज, फीस या शाश्तिः के उद्देश्य संबंधित विवाद; या
(ii) किसी कारण से निर्धारण, पुनर्निर्देश का निर्णय गये किसी अन्य आदेश; या
(iii) फाइल की गयी कोई अपील, पुनरीक्षण, रिट याचिका या विशेष अनुमित याचिका;
या
(iv) आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग के समस्त विवद स्वीकृत की गई पुनरीक्षण कार्यवाही; या
(v) कर, व्याज, फीस या शाश्ति के संदर्भ के लिए आवेदन की सूचित करते हुए जारी किये गये बॉटिस या आदेश; या
(vi) किसी कर, व्याज, फीस या शाश्ति के अपेक्षित संदर्भ के लिए अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में जारी की गयी कारण बताए सूचना; या
(vii) अधिनियम के अधीन नियुक्त या विहिंड या प्राधिकृत किसी प्राधिकारी द्वारा कर, व्याज, फीस या शाश्ति की वसूली के लिए प्रारंभ की गयी या उसके समय लंबी कार्यवाही;
(ञ) "विवादित रक्ष" से कोई कर, व्याज, फीस या शाश्ति, जो विवादित है, अभियंत है;
(ट) "पराधिय मांग" से अधिनियम से संबंधित कोई मांग, जो मांग और संग्रहण रजिस्टर में लंबी है, अभियंत है;
३) "चरण" से सारणी-क के स्तम्भ संख्याक ३ के अनुसार अपेक्षित रकम के संदर्भ के लिए, निम्नलिखित सारणी में यथावर्तित अवधि अभिव्यक्त है :-

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र.सं.</th>
<th>चरण</th>
<th>अवधि</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>चरण-1</td>
<td>31.03.2021 तक</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>चरण-2</td>
<td>01.04.2021 से 30.06.2021</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>चरण-3</td>
<td>01.07.2021 से 30.09.2021</td>
</tr>
</tbody>
</table>

४) "कर" में प्रशमन रकम या कर के बदले में एकमुख राशि और छूट फीस सम्मिलित है; और
(२) "कुल परादेय मांग या कुल विवादित रकम" से किसी अधिनियम के अधीन व्यवहारी या व्यविधि से संबंधित समस्त परादेय मांग या विवादित रकम की कुल राशि अभिव्यक्त है; और
(२) इस स्कीम में प्रयुक्त किये गये किन्तु परिभाषित नहीं किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जैसा उन्हें उस अधिनियम में समनुदेशित किया गया है जिससे परादेय मांग या विवाद संबंधित है।

४. स्कीम के अधीन फायदे:- कर की छूट और ब्याज, शास्ति और फीस का अधित्यजन नीचे दी गयी सारणी-क के स्तम्भ संख्याक २ में यथावर्तित परादेय मांग या विवादित रकम के प्रवर्तन पर स्तम्भ संख्याक ३ में यथावर्तित शर्तों और इस स्कीम के खण्ड ५ में वर्णित शर्तों के पूर्ण किये जाने पर स्तम्भ संख्याक ४ में यथावर्तित सीमा तक होगा:-

<p>| कर की छूट और/या ब्याज, शास्ति और विलंब फीस के अधित्यजन के लिए |
|------------------|------------------|------------------|
| क्र. सं. | परादेय मांग या विवादित रकम का प्रबंधन | शर्तों | कर की छूट और/या ब्याज, शास्ति और विलंब फीस के अधित्यजन की सीमा |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>1</th>
<th>2</th>
<th>3</th>
<th>4</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>परादेय मांग या विवादित रकम किन्तु उनको अपेक्षित किया जायेगा, जो इस स्तर पर स्तम्भ संख्याक २, ३, ४ और ५ के अधीन आती हैं।</td>
<td>(i) चरण-1: आवेदक ने कर की रकम का ९० प्रतिशत जमा कर दिया हो। (ii) चरण-2: आवेदक ने कर की रकम का ९५ प्रतिशत जमा कर दिया हो। (iii) चरण-3: आवेदक ने कर की रकम का १०० प्रतिशत जमा कर दिया हो।</td>
<td>कर की शेष रकम, यदि कोई हो, स्कीम के अधीन आदेश की तारीख तक प्रदूषण ब्याज के साथ ब्याज, शास्ति और विलंब फीस की संपूर्ण रकम।</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>परादेय मांग जो घोषणा प्रस्तुत से संबंधित है किन्तु उनको</td>
<td>(i) चरण-1: आवेदक ने अंतर कर की रकम का २० प्रतिशत जमा कर दिया हो।</td>
<td>अंतर कर की शेष रकम, स्कीम के</td>
</tr>
</tbody>
</table>
अपवजित किया जायेगा, जो इस सारणी के क्रम संख्यांक 1, 3, 4 और 5 के अधीन आती हैं।

करा दिया हो।

(ii) चरण-II: आवेदक ने अंतर कर की रकम का 25 प्रतिशत जमा करा दिया हो।

(iii) चरण-III: आवेदक ने अंतर कर की रकम का 30 प्रतिशत जमा करा दिया हो।

अधीन आदेश की तारीख तक प्रोद्धृत व्याज के साथ व्याज, शास्ति और विलंब फीस, यदि कोई हो, की संपूणर् रकम।

3. परादेय मांग या विवादित रकम जो कर की दर, माल के वर्गीकरण या अधिनियम के निर्देश के तहत संबंधित है, किन्तु उनको अपवजित किया जायेगा, जो इस सारणी के क्रम संख्यांक 1, 2, 4 और 5 के अधीन आती हैं।

(i) चरण-1: आवेदक ने विवादित कर के 50 प्रतिशत के साथ स्वीकृत कर, यदि कोई हो, की संपूणर् रकम जमा करा दी हो।

(ii) चरण-II: आवेदक ने विवादित कर के 55 प्रतिशत के साथ स्वीकृत कर, यदि कोई हो, की संपूणर् रकम जमा करा दी हो।

(iii) चरण-III: आवेदक ने विवादित कर के 60 प्रतिशत के साथ स्वीकृत कर, यदि कोई हो, की संपूणर् रकम जमा करा दी हो।

विवादित कर की शेष रकम, रकम के अधीन आदेश की तारीख तक प्रोद्धृत व्याज के साथ व्याज, शास्ति और विलंब फीस, यदि कोई हो, की संपूणर् रकम।

4. परादेय मांग या विवादित रकम जो,-

(i) कर के अपवंचन या परिवर्तन; या

(ii) घोषणा प्रस्तुत (प्रस्तुत) / प्रमाणपत्र (प्रमाणपत्र) के दृष्टिकोण; या

(iii) लेखाओं में अंकित नहीं किये गए माल; या

(iv) अभिविन्दन में माल/यान; से संबंधित हैं; किन्तु उनको अपवजित किया जायेगा, जो इस सारणी के क्रम संख्यांक 1, 2, 3 और 5 के अधीन आती हैं।

(i) चरण-I: आवेदक ने परादेय शास्ति के 20 प्रतिशत के साथ कर की संपूणर् रकम जमा करा दी हो।

(ii) चरण-II: आवेदक ने परादेय शास्ति के 25 प्रतिशत के साथ कर की संपूणर् रकम जमा करा दी हो।

(iii) चरण-III: आवेदक ने परादेय शास्ति के 30 प्रतिशत के साथ कर की संपूणर् रकम जमा करा दी हो।

स्कीम के अधीन आदेश की तारीख तक प्रोद्धृत व्याज के साथ व्याज, शास्ति और विलंब फीस, यदि कोई हो, की संपूणर् रकम और शास्ति की शेष रकम।

5. कुल परादेय मांग या विवादित रकम जो अनल्य रूप से केवल व्याज और/या शास्ति से संबंधित है, और पच्चीस करोड़ रुपये से

(i) चरण-I: आवेदक ने व्याज और/या शास्ति का 40 प्रतिशत जमा करा दिया हो।

(ii) चरण-II: आवेदक ने व्याज स्कीम के अधीन आदेश की तारीख तक प्रोद्धृत व्याज के साथ व्याज
स्पष्टीकरण:

<table>
<thead>
<tr>
<th>अधिक है किन्तु उनको अपविष्ट किया जायेगा, जो इस सारणी के क्रम संख्याओं 1, 2, 3 और 4 के अधीन आती हैं।</th>
<th>और/या शास्ति का 45 प्रतिशत जमा करा दिया हो।</th>
<th>और/या शास्ति की शेष रकम।</th>
</tr>
</thead>
</table>

(iii) चरण-III: आवेदक ने इयाज और/या शास्ति का 50 प्रतिशत जमा करा दिया हो।

(1) जहां कोई व्यवहारी चरण-I, II या, यथास्थितिः, III की कालावधि के दौरान स्कीम के फायदे उपभोक्ता करने के लिए अपनी रजामंदी सूचित करता है और उस दिन से, जिसको निर्धारण प्राधिकारी स्कीम के अधीन संदर्भ की जाने अपेक्षित शुद्ध रकम सूचित करता है, उस दिन के भीतर या क्रमिक चरणों की अतिम तारीख से पूर्व, जो भी परवर्ती हो, अपेक्षित रकम जमा करा देता है, तब उस चरण में उपलब्ध फायदों का पात्र होगा जिसमें उसके अपनी रजामंदी सूचित की है। यदि, व्यवहारी उपयुक्त विनिर्दिष्ट समय में शुद्ध रकम जमा कराने में असफल रहता है, तब वह उस चरण में फायदे के लिए पात्र होगा, जिसमें उसने उक्त रकम जमा की है और स्कीम की प्रवतर्न कालावधि से परे व्यक्तिक की निर्धारण के मामले में, वह स्कीम के अधीन किसी फायदे के लिए पात्र नहीं होगा।

(2) जहां कोई रकम मांग के विस्तार, उसके सृजन के पश्चात्, इस स्कीम के जारी होने से पूर्व जमा की गयी है और यदि अपविष्ट पादेय मांग के लिए विकल्प प्रस्तुत किया जाता है, वहां पूर्व में जमा रकम को, यदि चालान में विनिर्देश रूप से वर्गित नहीं है, तो प्रथमत: यह कर दायित्व के विस्तार, तत्पश्चात् क्रमशः व्याज, शास्ति और विलम्ब फीस के दायित्व के विस्तार समायोजित की जायेगी। तथापि यदि किसी न्यायालय आदेश की अनुपालना में कोई रकम जमा की गयी है तो वह तदनुसार समायोजित की जायेगी।

(3) जहां किसी व्यवहारी या व्यक्ति ने एमनेस्टी स्कीम-2017, प्रवेश कर के लिए नई स्वीचित एमनेस्टी स्कीम-2017, मोटर यानों के प्रवेश पर कर के लिए एमनेस्टी स्कीम-2017, मनोरंजन कर के लिए एमनेस्टी स्कीम-2017 या विलास कर के लिए एमनेस्टी स्कीम-2017 के अधीन आदेश की अनुपालना की जा रही है, स्कीम या उक्त स्कीम(स्कीमों) के अधीन कोई रकम जमा की थी किन्तु किसी फायदे से संबंधित स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त नहीं कर सका था, ऐसे मामलों में दे व्यक्ति/व्यवहारी इस स्कीम के अधीन फायदों के लिए पात्र हों और उन स्कीमों के अनुसरण में जमा रकम, इस स्कीम के अधीन फायदे के लिए समायोजित और अनुज्ञेय होगी।

(4) जहां मांग के विविध रकम पूर्ण रूप से व्याज और/या शास्ति और/या विलम्ब फीस को समायोजित करती है, वहां ऐसे मामलों में कर की रकम जमा की गयी समझी जायेगी।

(5) जहां 30.06.2017 तक की अवधि से संबंधित मांग या विविध रकम पूर्ण में ही जमा कर दी गयी है और उससे संबंधित व्याज के लिए मांग उद्देश्यणी है किन्तु उद्देश्यीत नहीं की गयी है, वहा ऐसे मामलों में स्कीम के अधीन आदेश की तारीख तक प्रोटूडुम
भाग 4(ग) राजस्थान राज-पत्र, फरवरी 24, 2021 860

व्याज के साथ संदेह व्याज का उपयुक्त सारणी-क के अनुसार अधिस्पर्श किया जायेगा।

(6) मांग या विवादित रकम के प्रवर्तक के लिए जहां व्यवहारी या चक्कर से उपयुक्त सारणी-क के अनुसार कोई रकम जमा करने की अपेक्षा नहीं की गयी है, वहाँ ऐसे मामलों में, वह निर्धारण प्राधिकारी को उसकी सूचना दे सकेगा। ऐसे मामलों में जहां व्यवहारी या चक्कर से उपयुक्त सारणी-क के अनुसार की अपेक्षा नहीं होती है, निर्धारण प्राधिकारी मामले को अपने स्तर पर निपटाने के लिए अवगत हो सकेगा।

(7) घोषणा प्रवर्तक से संबंधित मांग या चक्कर रकम के लिए, जहां 30.06.2021 तक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, वहाँ स्कीम की प्रवर्तन कालावधि के भीतर वसूली कार्यालयों या संलग्न व्यवसायों के अनुसार संख्यांक 2 के सामने उपयुक्त संख्यांक 3 के अनुसार चरण-III में जमा की जायेगी वाली अपेक्षित रकम के समतुल्य बैंक गारंटी के रूप में प्रतिबद्ध प्रस्तुत कर देता है।

(8) जहां मांग, जिसके लिए चक्कर से चक्कर स्कीम के अधिकार विकल्प लेने का आशय रखता है, से संबंधित परिसंदृष्टि के लिए कोई आवेदन संबंधित निर्धारण चक्करी के समस्त लंबित है, तब ऐसे चक्कर के चक्कर से लिखित में संसूचना पर उसे ऐसी संसूचना से सात दिन के भीतर या प्रवर्तन कालावधि तक, जो भी पहले हो, निपटायेगा।

(9) ऐसे मामलों में, जो विवाद में हैं और जिनके लिए मांग और संग्रहण रजिस्टर में कोई मांग परदेश नहीं हैं, कर, व्याज, विल्म्ब फीस और/या शास्त्री की रकम उक्त विवाद के संबंध में ज़रूर किये गये मूल निर्धारण आदेश या नोटिस के अनुसार संबंधित जारी होगी। ऐसे मामलों में संबंधित निर्धारण प्राधिकारी स्वयं के समस्त लंबित कार्यालयी, यदि कोई हो, को प्रत्याहार करेगा या इस स्कीम की प्रवर्तन कालावधि के भीतर उपयुक्त सारणी-क के अनुसार लंबित रकम के जमा किये जाने के पश्चात् किसी न्यायालय या कर बोर्ड या, यथास्थिति, अपील प्राधिकारी के समस्त लंबित मामले के प्रत्याहार के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(10) जहां चक्कर के चक्कर द्वारा विवरणों या लेख पुस्तकों में तथ्यों को छिपाया गया है, कपटपूर्ण या दुर्व्यवस्था किया गया है, ऐसे मामले उपयुक्त सारणी-क के क्रम संख्यांक 3 के अधीन नहीं आयेगे।

5. शर्तें: इस स्कीम के फायदे निम्नलिखित शर्तों को पूरा किये जाने पर उपलब्ध होंगे, अर्थातः

(i) आवेदक ने इस स्कीम की प्रवर्तन कालावधि के भीतर उपयुक्त सारणी-क के समतुल्य संख्यांक 3 के अनुसार या, यथास्थिति, उपयुक्त स्पष्टीकरण (1) के अनुसार अपेक्षित रकम जमा करा दी है;

(ii) आवेदक ने किसी न्यायालय या कर बोर्ड या, यथास्थिति, अपील प्राधिकारी के समस्त लंबित मामले, यदि कोई हो, के प्रत्याहार के लिए आवेदन इस स्कीम की प्रवर्तन कालावधि के भीतर प्रस्तुत कर दिया है; और
राजस्थान राज-पत्र, फरवरी 24, 2021
भाग 4(ग)

(iii) पूर्व में किये गये किसी अधिक संदाय का प्रतिदाय इस स्कीम के अधीन कर की छूट और/या अधित्यजन के कारण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

6. फायदा प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया.- (1) इस स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए आवेदक संबंधित निर्धारण प्राधिकारी को इस संदेह में वाणिज्यिक कर विभाग की वेबसाइट www.rajtax.gov.in पर उसकी रजामंदी इलेक्ट्रानिक रूप से सूचित करेगा।

(2) पृथक अधिनियमों के अधीन साथ ही पृथक निर्धारण प्राधिकारियों के समक्ष लंबित मांगो/विवाद के लिए रजामंदी की पृथक-पृथक सूचना देगा।

(3) इस स्कीम के अधीन फायदों का चयन करने वाले किसी व्यवहारी या व्यक्ति के मामले में निर्धारण प्राधिकारी, व्यवहारी या व्यक्ति के विस्तृत लंबित मांग(संग) और विवादित रकम के व्यवहार इस स्कीम के अनुसार में किये जाने वाले संदाय और प्रोटकॉर्ट किये जाने वाले पारिवारिक फायदों सहित इलेक्ट्रानिक रूप से सूचित करेगा।

(4) इस स्कीम के अधीन फायदे प्राप्त करने के लिए व्यवहार व्यक्ति और स्थानीकारण, यदि कोई हो, ऐसे होंगे जो आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान द्वारा अधिसूचित किये जायें।

(5) सारणी-क के क्रम यथायथ 1 से 5 के अधीन परादेय मांग या विवाद के प्रवांकारण से संबंधित किसी विवाद की दशा में आयुक्त, वाणिज्यिक कर का विनिमय अंतिम होगा।

[प.12(29)वित्त/कर/2021-269]
राजपत्र के आदेश से,

(टीमा डबी)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिशासन
जयपुर, फरवरी 24, 2021

एस.ओ.452.-राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 9) की धारा 174 की उप-धारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये तुरंत प्रभाव से प्रभाव होंगे।

2. नियम 21 का संशोधन.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006, जिसे इसके पश्चात उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 21 में,-
भाग 4(ग) राजस्थान राज-पत्र, फरवरी 24, 2021

(i) उप-नियम (1) के विद्यमान द्वितीय परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् नील--

"परन्तु यह और कि 30.06.2017 तक की किसी कालावधि से संबंधित निर्धारणों के लिए, व्यवहारी 30.06.2021 तक घोषणा प्रथा या प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर सकेगा।"

(ii) उप-नियम (1) का विद्यमान तृतीय परन्तुक हटाया जायेगा; और

(iii) उप-नियम (8) के विद्यमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् --

"परन्तु यह और कि व्यवहारी 30.06.2017 तक की किसी कालावधि से संबंधित ऐसा कोई आवेदन, 30.06.2021 तक सीधे ही संबंधित निर्धारण प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकेगा और निर्धारण प्राधिकारी ऐसे आवेदन का इस उप-नियम के उपबंध के अनुसार अपने स्तर पर निपटाया करेगा।"

3. नियम 40 का संशोधन - उक्त नियमों के नियम 40 में-

(i) उप-नियम (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "उस दिन से जिस दिन संकमर्श संबंधि (संविदा) की सकल रकम दस लाख रुपये से अधिक हो जाता है या 31.12.2020 तक, जो भी पश्चात्त्वत हो।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "उस दिन से जिस दिन संकमर्श संबंधि (संविदा) की सकल रकम दस लाख रुपये से अधिक हो जाती है या 30.06.2021 तक, जो भी पश्चात्त्वत हो।" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) इस प्रकार संशोधित उप-नियम (1) में, निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् नील--

"परन्तु जहां अवाडर कोई सरकारी विभाग, या कोई निगम, कंपनी, लोक उपक्र, सहकारी सोसाइटी, स्थानीय निकाय, कानूनी निकाय या स्वशासी निकाय है जिसमें सरकार की शेयर पूंजी है, ऐसे अवाडर के लिए 30.06.2017 तक की किसी कालावधि से संबंधित अवाडर पत्रपत्र प्राप्ति करना आज्ञापक नहीं है।"

(iii) उप-नियम (8क) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "तिमाही की समाप्ति से तीस दिन के भीतर या 31.12.2020 तक, जो भी पश्चात्त्वत हो।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "तिमाही की समाप्ति से तीस दिन के भीतर या 30.06.2021 तक, जो भी पश्चात्त्वत हो।" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iv) उप-नियम (8ख) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "सुसंगत वर्ष की समाप्ति से तीन मास के भीतर या 31.12.2020 तक, जो भी पश्चात्त्वत हो।", के स्थान पर अभिव्यक्ति "सुसंगत वर्ष की समाप्ति से तीन मास के भीतर या 30.06.2021 तक, जो भी पश्चात्त्वत हो।" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(v) विद्यमान उप-नियम (11) के अंत में आने वाले विद्यमान विराम चिन्ह "।" के स्थान पर विराम चिन्ह "।:" प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(vi) इस प्रकार संशोधित उप-नियम (11) में, निम्नलिखित नये परन्तुक जोड़े जायेंगे, अर्थात्--

"परन्तु जहां अवाडर सरकारी विभाग या कोई निगम, कंपनी, लोक उपक्र, सहकारी सोसाइटी, स्थानीय निकाय, कानूनी निकाय या स्वशासी निकाय है जिसमें निम्नलिखित नये परन्तुक जोड़े जायेंगे, अर्थात्--
सरकार की शेयर पूंजी है और अवार्ड पहचान प्रमाणपत्र अभिप्राप्त नहीं किया है, वह संविदाकार को व्यक्तिश: सम्यक रूप से भरा हुआ प्रस्तुत मूपक-41 जारी करेगा और संविदाकार उसे संबंधित निर्धारण प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा:
परन्तु यह और कि जहाँ ऐसे अवार्ड ने संविदाकार को व्यक्तिश: प्रस्तुत मूपक-41 पहले ही जारी कर दिया है और संविदाकार 23 फरवरी, 2021 को या उससे पूर्व संबंधित निर्धारण प्राधिकारी को उसे प्रस्तुत कर चुका है, ऐसे मामलों में नया प्रस्तुत मूपक-41 प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।"

4. प्रस्तुत मूपक-41 का प्रतिस्थापन: उक्त नियमों के संलग्न विद्यमान प्रस्तुत मूपक-41 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः -
"प्रस्तुत मूपक-41 [नियम 40(11) देखिए]
अवार्ड द्वारा स्रोत पर कटौती का प्रमाणपत्र

प्रस्तुत सं.
जारी करने की तारीख:

| संविदाकार का नाम | 
| --- | --- |
| रजिस्ट्रेटर करण सं. (टिन), यदि कोई हो | पता |
| अवार्ड का नाम | अवार्ड पहचान सं., यदि कोई हो |
| पता | संविदाकार को संदाय की गयी रकम |
| टीडीएस की रकम |

अवार्ड द्वारा स्रोत पर कर कटौती के ब्योरी

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र. सं.</th>
<th>कार्यान्वयन संख्या</th>
<th>कार्यान्वयन दिनांक</th>
<th>संविदा की प्रकृति</th>
<th>संविदा का सकल मूल्य</th>
<th>बिल सं. और तारीख</th>
<th>बिल की रकम</th>
<th>संविदाकार का ई.सी. सं., यदि कोई हो</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
<td>7</td>
<td>8</td>
</tr>
</tbody>
</table>

स्रोत पर कटौती की रकम

| स्रोत पर कटौती की रकम | संविदाकार को संदाय की जमा की वाचर सं. और तारीख | चालान की सकल रकम और तारीख जिसको स्रोत पर कटौती किया गया कर वाणिज्यिक कर विभाग के खाते में जमा कराया गया | एजी समायोजन/जीआरएन/ सीआईएन के माध्यम से किये गये संदायों के लिए कोषाल्य वाचर संख्यांक |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 10 | 11 | 12 |
यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दी गयी जानकारी मेरे सर्वौत्तम ज्ञान के अनुसार पूर्ण, सत्य और सही है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

तारीख:
स्थान:
कर की कर्तृत्व और जमा के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर और मुहर विभाग/कार्यालय का नाम"

[प.12(29)वित्त/कर/2021-270]
राज्यपाल के आदेश से,

(टीना डाबी)
संयुक्त शासन सचिव

बित्त विभाग
(कर अनुमान)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 24, 2021

एस.ओ.453.-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 4 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोगहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-6 में इसके द्वारा तुरंत प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है, अथात्—

संशोधन
उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-6 में, विद्यमान क्रम संख्यांक 7 और उसकी प्रविधियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अथात्—

```
  7. पेट्रोलियम क्रूड 5
```

[प.12(29)वित्त/कर/2021-271]
राज्यपाल के आदेश से,

(टीना डाबी)
संयुक्त शासन सचिव
वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 24, 2021
एस.ओ.454.-राजस्थान स्टॉपम अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना संदर्भक प.2(55)वित्त/कर/2012-13 दिनांक 12.07.2012, प.4(3)वित्त/कर/ 2018-188 दिनांक 12.02.2018, प.4(3)वित्त/कर/2017-113 दिनांक 08.3.2017, प.2(37)वित्त/ कर/2010-125 दिनांक 08.03.2011, प.4(4)वित्त/कर/2020-126 दिनांक 20.02.2020 और प.4(4)वित्त/कर/2020-127 दिनांक 20.02.2020 को अतिरिक्त करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ संख्यांक 2 में विनिर्दिष्ट लिखित के प्रभार शून्य घटाया जाए और उनके प्रत्येक के सामने उक्त सारणी के स्तम्भ संख्यांक 3 में यथाविनिर्दिष्ट दर से प्रभावित किया जायेगा:-

<table>
<thead>
<tr>
<th>सारणी</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>क्र.सं.</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>इकाई इत्यादि के लिए भू-खण्ड के प्रथम आबंटन के मामले में</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------------------------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>(ii) वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए भू-खण्ड के प्रथम आबंटन के मामले में</td>
</tr>
</tbody>
</table>

7. राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-K के अधीन स्थानीय प्राधिकारियों के निपटान के लिए रखी गयी भूमि के संबंध में जारी/निष्पादित पट्टा विलेख

8. राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, लोक उपक्रम या अन्य किसी सरकारी निकाय द्वारा आवश्यक या उनके द्वारा विक्रीत भूमि के संबंध में जारी/निष्पादित पट्टा विलेख (जो उपर्युक्त क्रम संख्यांक 1 से 7 में विनिर्दिष्ट किसी प्रवर्ग के अधीन नहीं आता है)

9. क्रम संख्यांक 2 से 8 के अन्तर्गत आने वाली कोई पट्टा विलेख, जो पुनर्विधानमंत्रकरण के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रततुल किया गया हो

प्रियियम की रकम और व्यापक प्रभार या शासित, यदि कोई हो, को समझित करते हुए प्रतिफल के रूप में संदर्भ अन्य प्रभार और दो वर्ष के किराये की औसत रकम पर हस्तान्तरण की दर से।

प्ररमण:-1. राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 या 158 या राजस्थान सरकारी अनुदान अधिनियम, 1961 या राजस्थान स्लाम डेवलपमेंट पॉलिसी-2012 या मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 या प्रधानमंत्री आवास योजना या राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2010 के अधीन जारी/निष्पादित पट्टा विलेख/विक्रय विलेख के मामले में आबंटी, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समाधानपद रूप में यह साबित करेगा कि पट्टा विलेख/विक्रय विलेख ऐसे अधिनियम, नियम, योजना या, यथास्थिति, पॉलिसी के अधीन जारी/निष्पादित किया गया है।

2. यह अधिसूचना, निष्पादित लिखित या रजिस्ट्रीकरण या निर्देश के लिए उप-रजिस्ट्रार के समक्ष या स्टाम्प शुल्क के न्यायनिर्णय या लागू करने के लिए कलक्टर (स्टाम्प) या अन्य किसी न्यायालय के समक्ष लंबित लिखित पर लागू होगी किन्तु न्यायालय की प्रतिदाय पर नहीं किया जायेगा।

[प.4(2)वित्त/कर/2021-272]

राज्यपाल के आदेश से,

(टीना डाबी)
संयुक्त शासन सचिव
एस.ओ.455.-राजस्थान स्ट्याम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना संख्याक प.4(15)दिनांक 14.07.2014 को अंतिमित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि निम्नलिखित लिखितों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और निम्नलिखित प्रधानियत किया जायेगा:-

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र.सं.</th>
<th>लिखित का विवरण</th>
<th>हस्तान्तरण पत्र की दर से संदेह स्टाम्प शुल्क</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, लोक उपक्रम या अन्य किसी सरकारी निकाय द्वारा आयुक्त या विक्रेता भूमि के संबंध में आबंटन आदेश के आधार पर पूर्वक निष्पादित प्राथमिक मध्यस्तरीय अरजिस्त्रीकृत और असम्यक रूप से स्टाम्पित लिखित।</td>
<td>संपत्ति के बाजार मूल्य के स्थान पर भूल आबंटन की रकम का 1.5 गुना पर, इस शत के अद्ध्यौद्ध में रहते हुए या स्टाम्प 2 में उल्लिखित संबंधित प्राधिकारी उस स्थान संपत्ति के संबंध में निष्पादित अरजिस्त्रीकृत और असम्यक रूप से स्टाम्पित लिखितों की संख्या का विवरण देते हुए एक प्रमाणपत्र जारी करेगा और पद्धारोपक उसके पद्ध मिलेख प्राप्त करने से पूर्व अपरीक्षित गर्भसाधन अरजिस्त्रीकृत और असम्यक रूप से स्टाम्पित लिखित।</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>नगरीय स्थानीय निकायों से पद्ध मिलेख प्राप्त करने से पूर्व आबंटन सहवार सोंसाइटों द्वारा आयुक्त या विक्रेता भूमि के संबंध में निष्पादित प्राथमिक मध्यस्तरीय अरजिस्त्रीकृत और असम्यक रूप से स्टाम्पित लिखित।</td>
<td>हस्तान्तरण पत्र की दर से संदेह स्टाम्प शुल्क प्रधानियत की संख्या के प्रति, रजिस्त्रकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(i) जहां दस्तावेज 31 मार्च, 1995 तक निष्पादित हुआ है, वहाँ उप-पंजीयक के समक्ष प्रस्तुत करण की तारीख को या, यथास्थिति, कलक्टर (स्टाम्प) को निर्देश की तारीख को संपत्ति के बाजार मूल्य के 10 प्रतिशत पर;  

(ii) जहां दस्तावेज 1 अप्रैल, 1995 से 31 मार्च, 2005 के मध्य निष्पादित हुआ है, वहाँ उप-पंजीयक के समक्ष प्रस्तुत करण की तारीख को या, यथास्थिति, कलक्टर (स्टाम्प) को निर्देश की तारीख को संपत्ति के बाजार मूल्य के 20 प्रतिशत पर;  

(iii) जहां दस्तावेज 1 अप्रैल, 2005 से 31 मार्च, 2010 के मध्य निष्पादित हुआ है, वहाँ उप-पंजीयक के समक्ष प्रस्तुत करण की तारीख को या, यथास्थिति, कलक्टर (स्टाम्प) को निर्देश की तारीख को संपत्ति के बाजार मूल्य के 30 प्रतिशत पर;
[(iv) जहां दस्तावेज 1 अप्रैल, 2010 से 14 जुलाई, 2014 के मध्य निष्पादित हुआ है, वहाँ उप-पंजीयक के समस्त प्रस्तुतीकरण की तारीख को या, यथास्थिति, कलक्टर (स्टाम्प) को निर्देश की तारीख को संपत के बाजार मूल्य के 35 प्रतिशत पर;
(v) जहां दस्तावेज 15 जुलाई, 2014 को या उसके पश्चात् निष्पादित हुआ है, वहाँ उप-पंजीयक के समस्त प्रस्तुतीकरण की तारीख को या, यथास्थिति, कलक्टर (स्टाम्प) को निर्देश की तारीख को संपत के बाजार मूल्य के 40 प्रतिशत पर;

टिप्पण: 1. पट्रा विलेख जारी करते समय संबंधित नगरीय स्थानीय निकाय, ऐसी स्थावर संपत के संबंध में निष्पादित मध्यवर्ती अरडंस्ट्रीकृत और असम्यक रूप से स्टाम्पित लिखतों के निष्पादन की तारीख सहित उनकी संख्या वर्णित करते हुए एक प्रमाणपत्र जारी करेगा और ऐसी मध्यवर्ती लिखतों की प्रतियां भी उपलब्ध करवायेगा;
2. पट्राधारक उसके पट्रा विलेख के साथ रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समस्त ऐसे प्रमाणपत्र और अरडंस्ट्रीकृत और असम्यक रूप से स्टाम्पित लिखतों की प्रतियां प्रस्तुत करेगा।

[प.4(2)विल्त/कर/2021-273]
राज्यपाल के आदेश से,

(टीना डाबी)
संयुक्त शासन सचिव

विल्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 24, 2021

एस.ओ.456.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की समय-समय पर
यथासंशोधित अधिसूचना संख्यांक प.12(11)वित्त/कर/2013-116 दिनांक 06.03.2013 को अस्तित्व में आए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहिंत में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि-

(i) पिता, माता, पुत्र, भाई, बहिन या पति के पक्ष में निष्पादित स्थावर संपत्ति के दान विलेखों प्रबर्त लालेख शुल्क घटाया जायेगा और संपत्ति के बाजार मूल्य के 2.5 प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जायेगा;

(ii) पुत्री या पुत्रवधू के पक्ष में निष्पादित स्थावर संपत्ति के दान विलेखों पर प्रबर्त लालेख शुल्क घटाया जायेगा और संपत्ति के बाजार मूल्य के एक प्रतिशत की दर से या एक लाख रुपये, जो भी कम हो, प्रभारित किया जायेगा;

(iii) पत्नी के पक्ष में निष्पादित स्थावर संपत्ति के दान विलेखों पर प्रबर्त लालेख शुल्क घटाया जायेगा और संपत्ति के बाजार मूल्य के एक प्रतिशत की दर से या एक लाख रुपये, जो भी कम हो, प्रभारित किया जायेगा;

(iv) पुत्र का पुत्र, पुत्र की पुत्री, पुत्री का पुत्र या पुत्री की पुत्री के पक्ष में निष्पादित स्थावर संपत्ति के दान विलेखों पर प्रबर्त लालेख शुल्क से छूट दी जायेगी; और

(v) विधवा के पक्ष में,-

(क) उसके मृत पति की माता, पिता, भाई या बहिन; या
(ख) उसकी स्वयं की माता, पिता, भाई, बहिन, पुत्र या पुत्री;

द्वारा निष्पादित स्थावर संपत्ति के दान विलेखों पर प्रबर्त लालेख शुल्क से छूट दी जायेगी।

[प.4(2)वित्त/कर/2021-274]
राज्यपाल के आदेश से,

(टीना डाबी)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 24, 2021

एस.ओ.457-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना संख्यांक प.4(6)वित्त/कर/2016-269 दिनांक 30.03.2016 को अस्तित्व में आए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहिंत में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि उक्त अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 48 के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट पैतृक
संपत्ति के निर्मूलित विलेख पर प्रभाव रस्ता शुल्क घटाया जायेगा और निम्नानुसार प्रभावित किया जायेगा:-

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र.सं.</th>
<th>विवरण</th>
<th>रस्ता शुल्क की दर</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>जहां त्यांगे गये शेयर, हित, भाग या दावे का बाजार मूल्य 10 लाख रुपये से अधिक नहीं है।</td>
<td>पांच सौ रुपये</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>जहां त्यांगे गये शेयर, हित, भाग या दावे का बाजार मूल्य 10 लाख रुपये से अधिक है।</td>
<td>पांच हजार रुपये</td>
</tr>
</tbody>
</table>

यह अधिसूचना निष्पादित लिखितें या रजिस्ट्रीकरण या निर्देश के लिए उप-रजिस्ट्री के समक्ष या रस्ता शुल्क के न्यायनिर्णयन के लिए कलक्टर (रस्ता) या अन्य किसी न्यायालय के समक्ष लंबित लिखितें पर भी लागू होगी किन्तु पूर्व में संदर्भ रस्ता शुल्क का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

[प.4(2)विल्च/कर/2021-275]
राज्यपाल के आदेश से,

(टीमा डाबी)
संयुक्त शासन सचिव

विवरण
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 24, 2021

एस.ओ.458-राजस्थान रस्ता अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत शब्दियों का प्रयोग करते हुए और इस विवरण की अधिसूचना संख्यांक प.4(3)विल्च/कर/2017-109 दिनांक 08.03.2017 को अतिलिखित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना संभवौ छेत्र्य है, इसके द्वारा आदेश देती है कि भागीदारी फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या अंशवानित दायित्व भागीदारी में या विपयर्येन संपरिवर्तन से संबंधित लिखत पर प्रभाव रस्ता शुल्क घटाया जायेगा और 0.5 प्रतिशत की दर से प्रभावित किया जायेगा।

[प.4(2)विल्च/कर/2021-276]
राज्यपाल के आदेश से,

(टीमा डाबी)
संयुक्त शासन सचिव
वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 24, 2021

एस.ओ.459.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि चार तलाव से अधिक के बहुमंजिला भवन में प्लैट या आवासीय इकाई, जिसका बाजार मूल्य पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है, से संबंधित हस्तान्तरण विलेख, यदि ऐसा हस्तान्तरण विलेख 30.06.2021 तक निष्पादित और रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत कर दिया जाता है, पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और चार प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जायेगा।

[प.4(2)वित्त/कर/2021-277]
राज्यपाल के आदेश से,

(टीना डाबी)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 24, 2021

एस.ओ.460.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.1(11)वित्त/कर अनु.97 दिनांक 21.03.1998 को आंशिक रूप से परिवर्तित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि उक्त अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 50 में विनिर्दिष्ट लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और अधिकतम पचास लाख रुपये के अध्यधीन रहते हुए 0.1 प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जायेगा।

[प.4(2)वित्त/कर/2021-278]
राज्यपाल के आदेश से,

(टीना डाबी)
संयुक्त शासन सचिव
भाग 4(ग) राजस्थान राज-पत्र, फरवरी 24, 2021
872

बित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 24, 2021

एस.ओ.461.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 86 और 87 और भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) की धारा 74 द्वारा पद्धति शिक्षितों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) नियम, 2021 है।
(2) ये तुरंत प्रकृत होंगे।
2. नये नियम 29-ख का अंतःस्थापन.- राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के विद्यमान नियम 29-क के पश्चात और विद्यमान नियम 30 से पूर्व, निम्नलिखित नया नियम अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थातः:-

"29-ख. ई-स्टाम्प प्रमाणपत्रों पर डिस्काउंट और पारिशमिक.- (1) राज्य में स्टाम्प शुल्क प्रशासन प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा शुल्क संग्रह एजेंशी की शुल्क संग्रह एजेंशी, जिसे इसमें इसके पश्चात एजेंशी के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, को-
(i) ई-स्टाम्पों के विक्रय के माध्यम से संग्रहीत रकम के 0.65 प्रतिशत से अधिक की किसी रकम की, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाये, कटौती अनुज्ञात की जायेगी; और
(ii) प्राधिकृत संग्रहण केंद्रों के माध्यम से विक्री ई-स्टाम्पों के संबंध में, नियम 29 और 29-क के अधीन स्टाम्प विक्रेताओं का अनुज्ञात रकम के बराबर रकम की कटौती अनुज्ञात की जायेगी।
(2) एजेंशी, ई-स्टाम्पों के विक्रय के माध्यम से उसके द्वारा संग्रहीत रकम में से उप-नियम (1) के अधीन अनुज्ञात रकम की कटौती करेगी और उसके द्वारा नियुक्त प्राधिकृत संग्रहण केंद्रों को ई-स्टाम्पों के विक्रय के माध्यम से उनके द्वारा संग्रहीत रकम के अनुपात में उप-नियम (1) के खण्ड (ii) के अधीन अनुज्ञात रकम का संदर्भ करेगी।
(3) एजेंशी, उप-नियम (2) के अधीन कटौती की गयी और संदर्भ रकम का सैमासिक विवरण महानिरीक्षक, स्टाम्प को प्रस्तुत करेगी।"

[प.4(2)बित्त/कर/2021-279]
राज्यपाल के आदेश से,

(टीना डाबी)
संयुक्त शासन सचिव
बित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 24, 2021
एस.ओ. 462.- राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उप-नियम (1) के खण्ड (ख) और उप-नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना संख्यांक प.4(4)विल्क/कर/2015-226 दिनांक 09.03.2015 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, संपूर्ण राज्य के लिए भूमि के निम्नसिविधत प्रवर्तन के कार्य के निर्धारण के लिए इसके द्वारा निम्नानुसार दर्ज अनुपात करती है :-
1. औद्योगिक प्रयोजनों के लिए भूमि की दरें
रीको औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक भूमि या औद्योगिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तित भूमि या औद्योगिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की जा रही कृषि भूमि की दरें:-
(i) रीको औद्योगिक क्षेत्र में रीको द्वारा अवधारित दरों के समतुल्य होंगी; और
(ii) अन्य मामलों में उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दरों के तीन गुना के समतुल्य होंगी किन्तु यदि ऐसे दरे निकटतम रीको औद्योगिक क्षेत्र में रीको द्वारा अवधारित दरों से अधिक हैं तब उस निकटतम रीको औद्योगिक क्षेत्र में रीको द्वारा अवधारित दरों के समतुल्य होंगी।
2. रीको औद्योगिक क्षेत्र में संस्थानिक, आवासीय और व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए भूमि की दरें
रीको औद्योगिक क्षेत्र में संस्थानिक, आवासीय और वाणिज्यिक भूमि की दरें:-
(i) संस्थानिक भूमि के मामले में, रीको द्वारा अवधारित औद्योगिक भूमि की दरों के समतुल्य होंगी;
(ii) आवासीय भूमि के मामले में, रीको द्वारा अवधारित औद्योगिक भूमि की दरों के दो गुना के समतुल्य होंगी; और
(iii) वाणिज्यिक भूमि के मामले में, रीको द्वारा अवधारित औद्योगिक भूमि की दरों के चार गुना के समतुल्य होंगी।
3. रीको औद्योगिक क्षेत्र से बाहर संस्थानिक प्रयोजनों के लिए भूमि की दरें
संस्थानिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तित भूमि या संस्थानिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की जा रही कृषि भूमि की दरें:-
(i) जहां भूमि सहकारी सोसाइटियों/पूर्त संस्थाओं द्वारा क्रय की गयी है, उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दर के दोगुना के समतुल्य होंगी; और
(ii) अन्य मामलों में उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दर के दोगुना के समतुल्य होंगी।
स्पष्टीकरण: (i) ऐसे क्षेत्रों में जहां कृषि भूमि की दरों की जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश नहीं की गयी है वहां संस्थानिक भूमि की दर उस क्षेत्र की आवासीय भूमि की दरों के समतुल्य होंगी।
(ii) संस्था में शैक्षिक संस्थाएं, प्रशिक्षण संस्थाएं, कोचिंग संस्थाएं, छात्रावास, अस्पताल, बैंक, वित्तीय संस्थाएं, बीमा कंपनियां इत्यादि सम्मिलित होंगी।
भाग 4(ग)  राजस्थान राज-पत्र, फरवरी 24, 2021  874

4. सौर ऊर्जा संयंत्र, सौर पार्क, पवन ऊर्जा संयंत्र या हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र के प्रयोजनों के लिए भूमि की दर

सौर ऊर्जा संयंत्र, सौर पार्क, पवन ऊर्जा संयंत्र या हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र के प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तित भूमि या सौर ऊर्जा संयंत्र, सौर पार्क, पवन ऊर्जा संयंत्र या हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की जा रही कृषि भूमि की दर उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दर के दो गुना के समतुल्य होगी किन्तु यदि ऐसी दर निकटतम रीतों और योग्यक्षेत्र में रीतों द्वारा अवधारित दरों से अधिक हैं तब उस निकटतम रीतों और योग्यक्षेत्र में रीतों द्वारा अवधारित दरों के समतुल्य होगी।

5. एयो-इण्डस्ट्रियल प्रयोजनों के लिए भूमि की दर

एयो-इण्डस्ट्रियल प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तित भूमि या एयो-इण्डस्ट्रियल प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की जा रही कृषि भूमि की दर उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दर के दो गुना के समतुल्य होगी।

6. खनन प्रयोजनों के लिए भूमि की दर

(i) खनन प्रयोजनों के लिए क्रय की गयी कृषि भूमि या ऐसी कृषि भूमि, जिसके संबंध में खनन प्रयोजनों के लिए भू-स्वामी और पट्टदेव के मध्य सहमति विशेष निष्पादित किया गया है, के मामले में उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दर के तीन गुना के समतुल्य होगी और जहां उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दर अवधारित नहीं की गयी हैं, इसे हुए क्षेत्र की कृषि भूमि की दर के तीन गुना के समतुल्य होगी; और
(ii) नया खनन पट्टा (वाहे नीलाम के माध्यम से या अन्य तरीकों पर किया गया हो), खनन पट्टे के नवीकरण या खनन पट्टे के अन्तरण के मामले में दर, उस क्षेत्र की कृषि भूमि के दर के चार गुना के समतुल्य होगी और जहां उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दर अवधारित नहीं की गयी हैं, तो उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दर के चार गुना के समतुल्य होगी।

स्पष्टीकरण: उपयुक्त दर निष्पादित लिखतों या रजिस्ट्रिकरण या निर्देश के लिए उप-रजिस्ट्रियल गठन या न्यायनिर्णय के लिए रजिस्ट्रि (स्टाम्प) या अन्य किसी न्यायालय के समक्ष संदेह निश्चित लिखतों पर प्रति मामले में संदेह राखने का प्रतिदिन नहीं किया जायेगा।

7. रिसोर्ट प्रयोजनों के लिए भूमि की दर

रिसोर्ट प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तित भूमि या रिसोर्ट प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की जा रही कृषि भूमि की दर,

(i) उस भाग, जिस पर सन्मान लिख किया गया है या संन्यास अनुसूची संस्मरित क्षेत्र, इनमें से जो भी अधिक हो, के लिए उस क्षेत्र की वाणिज्यिक भूमि की दर के समतुल्य होगी; और
(ii) भूमि के शेष भाग के लिए उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दर के दो गुना के समतुल्य होगी।

8. होटल, मोटल, गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट प्रयोजनों के लिए भूमि की दर

होटल, मोटल, गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तित भूमि या उपयुक्त प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की जा रही भूमि की दर उस क्षेत्र की वाणिज्यिक भूमि की दर के समतुल्य होगी।

9. मैरिज गाइड प्रयोजनों के लिए भूमि की दर
राजस्थान राज-पत्र, फरवरी 24, 2021
भाग 4(ग)

मैरिज गार्डन प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की जा रही कृष्ण भूमि या मैरिज गार्डन प्रयोजनों के लिए संपर्वित हुई भूमि की दर,-

(i) उस भाग, जिस पर संबंधित किया गया है या अधिकतम अनुज्ञत संबंधित क्षेत्र, इनमें से जो भी अधिक हो, के लिए उस क्षेत्र की वाणिज्यिक भूमि की दर के समतुल्य होगी; और
(ii) भूमि के शेष भाग के लिए उस क्षेत्र की आवासीय भूमि की दर के डेढ़ गुना के समतुल्य होगी।

10. कंपनियों, फामी हाउस द्वारा का क्रय की गयी कृष्ण भूमि की दर कंपनी, फामी या संस्था द्वारा का क्रय की गयी कृष्ण भूमि की दर उस क्षेत्र की कृष्ण भूमि की दर के समतुल्य होगी।

11. फामर हाउस प्रयोजन के लिए भूमि की दर फामर हाउस प्रयोजन के लिए प्रयुक्त की जा रही कृष्ण भूमि की दर कंपनी, फामी या संस्था द्वारा क्रय की गयी कृष्ण भूमि की दर उस क्षेत्र की कृष्ण भूमि की दर के समतुल्य होगी।

12. 3000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले आवासीय या वाणिज्यिक भूखंडों की दर 3000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले आवासीय या वाणिज्यिक भूखंडों की दर को ऐसे प्रबंध की भूमियों के लिए विद्यमान दरों से 5 प्रतिशत कम किया जायेगा।

13. कोने के भूखंडों की दर 1000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले कृष्ण भूमि के भूखंड को छोड़कर, कोने के भूखंडों की दर 10 प्रतिशत अधिक होगी।

14. ऐसी भूमि की दर जिनके लिए समर्पित भू-उपयोग पट्टा/पट्टा विलेख जारी किया गया है रिक्त भूमि के विकास या अन्तर्गत पर, जिसके लिए विकास प्राधिकरण या नगर सुधार न्यायालय या अन्य स्थानीय निकाय द्वारा समर्पित भू-उपयोग का पट्टा/ पट्टा विलेख जारी किया गया है, ऐसी भूमि की दर उस क्षेत्र की वाणिज्य भूमि की दर के 50 प्रतिशत के समतुल्य होगी।

15. विभिन्न भू-उपयोगों के अधीन भूमि की दर भूमि, जो उसके अनुमोदित उपयोग से मिलन प्रयोजन के लिए प्रयुक्त की जाती है, की दर इसके सावधानी उपयोग या इसके अनुमोदित उपयोग, जो भी अधिक हो, के प्रबंध की दर के समतुल्य होगी।
16. किसी विशिष्ट क्षेत्र की आवासीय और वाणिज्यिक भूमि की दरें जहां ऐसी भूमि की दरें जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश नहीं की गयी हैं
   (i) आवासीय भूमि की दरें उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दरों की तीन गुना होंगी; और
   (ii) वाणिज्यिक भूमि की दरें उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दरों की छह गुना होंगी।

17. नगरीय क्षेत्रों के उपांत पट्टी की सीमाओं के भीतर अवस्थित 1000 वर्गमीटर तक क्षेत्रफल वाली कृषि भूमि की दरें
   नगरीय क्षेत्रों या नगरयोग्य सीमाओं या राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 90-क में यथा-परिभाषित नगरीय क्षेत्रों के उपांत पट्टी में अवस्थित 1000 वर्गमीटर तक क्षेत्रफल वाली कृषि भूमि की दरें, उस क्षेत्र की आवासीय भूमि की दरों के समतुल्य होंगी।
   स्पष्टीकरण: (i) उपयुक्त दरें विवरण की लिखित पर लागू होंगी।
   (ii) जहां कृषि भूमि के विवरण की लिखित में, क्रेताओं की संख्या एक से अधिक है और किसी क्रेता का शेयर 1000 वर्गमीटर या उससे कम है, भूमि के ऐसे शेयर का मूल्य, उस क्षेत्र की आवासीय भूमि की दर से संगणित किया जायेगा।

18. नगरीय क्षेत्रों के उपांत पट्टी की सीमाओं से बाहर अवस्थित 500 वर्गमीटर तक क्षेत्रफल वाली कृषि भूमि की दरें
   राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 90-क में यथा-परिभाषित नगरीय क्षेत्रों के उपांत पट्टी के बाहर अवस्थित 500 वर्गमीटर तक क्षेत्रफल वाली कृषि भूमि की दरें, सीवाय वहां, जहां ऐसी भूमि एकल खसरा में समाविष्ट है या जहां ऐसी भूमि, संलग्न कृषि भूमि के खातेदार दलािा क्रय की गयी है, उस क्षेत्र की आवासीय भूमि की दरों के समतुल्य होंगी।
   स्पष्टीकरण: (i) उपयुक्त दरें विवरण की लिखित पर लागू होंगी।
   (ii) जहां कृषि भूमि के विवरण की लिखित में, क्रेताओं की संख्या एक से अधिक है और किसी क्रेता का शेयर 500 वर्गमीटर या उससे कम है, भूमि के ऐसे शेयर का मूल्य, उस क्षेत्र की आवासीय भूमि की दर से संगणित किया जायेगा।
   (iii) उपयुक्त दरें निपादित लिखितों पर या रजिस्टरीकरण या निर्देश के लिए उप-रजिस्ट्रार के समक्ष या स्टाम्प शुलक के न्यायनिष्ठान के लिए कलक्टर (स्टाम्प) या अन्य किसी न्यायालय के समक्ष लंबित लिखितों पर भी लागू होगी किन्तु पूर्व में संदर्भ स्टाम्प शुलक का प्रतिदिन नहीं किया जायेगा।

[प.4(2)विल्क/कर/2021-280]
राज्यपाल के आदेश से,
(टीना डाबी)
संयुक्त शासन सचिव
राजस्थान राज-पत्र, फरवरी 24, 2021  भाग 4(ग)

बिल्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 24, 2021

एस.ओ.463.-राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उप-नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होते हैं कि परिस्थितियों में ऐसा किया जाना अपेक्षित है, इसके द्वारा आदेश देती है कि आवासीय और वाणिज्यिक प्रवर्ग की भूमि की विद्यमान दर 24.02.2021 से पुन:अधिधारित की जायेगी और दस प्रतिशत घटायी जायेगी।

[प.4(2)बिल्त/कर/2021-281]
राज्यपाल के आदेश से,

(टीना डबी)
संयुक्त शासन सचिव

बिल्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 24, 2021

एस.ओ.464.-राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उप-नियम (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना संख्यांक प.4(4)बिल्त/कर/2015-225 दिनांक 09.03.2015 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा वे मानदंड विनिर्देश करती है जिनके आधार पर बहुमंजिला भवन के अधीन आनुपातिक भूमि का बाजार मूल्य निर्धारित किया जायेगा :-

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र.सं.</th>
<th>इकाई का विवरण</th>
<th>भूमि के मूल्यांकन की रीति</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>छत के अधिकार के बिना भू-तल पर किसी इकाई के अन्तरण पर</td>
<td>भूमि के निर्धारित बाजार मूल्य का 70 प्रतिशत</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>छत के अधिकार के बिना प्रथम या द्वितीय तल पर किसी इकाई के अन्तरण पर</td>
<td>भूमि के निर्धारित बाजार मूल्य का 60 प्रतिशत</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>छत के अधिकार के बिना तहखाना (बेसमेट) पर किसी इकाई के अन्तरण पर</td>
<td>भूमि के निर्धारित बाजार मूल्य का 50 प्रतिशत</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>छत के अधिकार के बिना तृतीय या उससे ऊपर के तल पर किसी इकाई के अन्तरण पर</td>
<td>भूमि के निर्धारित बाजार मूल्य का 40 प्रतिशत</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>छत के अधिकार के साथ किसी इकाई के अन्तरण पर</td>
<td>भूमि के निर्धारित बाजार मूल्य का 100 प्रतिशत</td>
</tr>
</tbody>
</table>
स्पष्टीकरण: (i) आनुपातिक भूमि के मूल्यांकन की दर, अनुमोदित ले-आउट प्लान में इकाई के विलिफिक उपयोग या इकाई के वास्तविक उपयोग, जो भी अधिक हो, के अनुसार अवधारित की जायेगी।
(ii) यह अधिसूचना निष्पादित लिखित या राजिस्ट्रीकरण या निर्देश के लिए उप-राजिस्ट्री के समक्ष या टाम्पर शुल्क के न्यायविनियोग के लिए कलक्टर (स्टाम्प) या अन्य किसी न्यायालय के समक्ष लंबित लिखित पर भी लागू होगी किन्तु पूर्व में संदर्भ टाम्पर शुल्क का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

[प.4(2)वित्त/कर/2021-282]  
राजधानी दूरे निर्देश से,

(टीना कुबरी)  
संयुक्त शासन सचिव  
वित्त विभाग  
(कर अनुभाग)  
अधिसूचना  
जयपुर, फरवरी 24, 2021  

एस.ओ.465.-राजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियां का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.2(17)वित्त/कर/2010/पार्ट-225 दिनांक 02.09.2020 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन  
उक्त अधिसूचना की सारणी में,-
क. स्तम्भ संख्यांक 4 और 5 में, क्रम संख्यांक 5 के सामने, विद्यमान अभिव्यक्ति
"(xvii) कल्याणपुर उप तहसील कल्याणपुर",
के पश्चात अभिव्यक्ति
"(xviii) धनाऊ तहसील धनाऊ"
जोड़ी जायेगी;
ख. स्तम्भ संख्यांक 5 में,-
(i) क्रम संख्यांक 8 के सामने, विद्यमान अभिव्यक्ति "उप तहसील बज्जू", के स्थान पर अभिव्यक्ति "तहसील बज्जू" प्रतिस्थापित की जायेगी; और
(ii) क्रम संख्यांक 12 के सामने, विद्यमान अभिव्यक्ति "उप तहसील मण्डवर", के स्थान पर अभिव्यक्ति "तहसील मण्डवर" प्रतिस्थापित की जायेगी;
ग. विद्यमान क्रम संख्यांक 16 और उसकी प्रविधियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-
<table>
<thead>
<tr>
<th>नं ।</th>
<th>जगपूर</th>
<th>जिला जगपूर</th>
<th>(i) जगपूर</th>
<th>तहसील जगपूर, तहसील आमेर, तहसील बससी, तहसील चाकसू, तहसील चौमू, तहसील दो०, तहसील अमवारामगढ़, तहसील फागी, तहसील सांगारे।</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(ii)</td>
<td>विराटनगर</td>
<td>तहसील विराटनगर</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(iii)</td>
<td>गोविन्दगढ़</td>
<td>उप तहसील गोविन्दगढ़</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(iv)</td>
<td>खेजरोली</td>
<td>उप तहसील खेजरोली</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(v)</td>
<td>मांजराबाद</td>
<td>तहसील मांजराबाद</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(vi)</td>
<td>किशनगढ़ रेनवाल</td>
<td>तहसील किशनगढ़ रेनवाल</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(vii)</td>
<td>कोटखावदा</td>
<td>तहसील कोटखावदा</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(viii)</td>
<td>कोटपुर कीले</td>
<td>तहसील कोटपुर कीले</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(ix)</td>
<td>सांभर</td>
<td>तहसील सांभर</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(x)</td>
<td>शाहपुरा</td>
<td>तहसील शाहपुरा</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(xi)</td>
<td>माधोराजपुरा</td>
<td>उप तहसील माधोराजपुरा</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(xii)</td>
<td>आंधी</td>
<td>उप तहसील आंधी</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(xiii)</td>
<td>तूंगा</td>
<td>उप तहसील तूंगा</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(xiv)</td>
<td>अमरसर</td>
<td>उप तहसील अमरसर</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(xv)</td>
<td>मनोहरपुर</td>
<td>उप तहसील मनोहरपुर</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(xvi)</td>
<td>पावटा</td>
<td>तहसील पावटा</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(xvii)</td>
<td>कालवाड़</td>
<td>उप तहसील कालवाड़</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

घ. क्रम संख्यांक 19 के सामने, स्तम्भ संख्यांक 5 में,-

(क) विद्यमान अभियंतक "उप तहसील सुनैल", के स्थान पर अभियंतक "तहसील सुनैल" प्रतिस्थापित की जायेगी; और
(ख) विद्यमान अभियंतक "उप तहसील बकानी", के स्थान पर अभियंतक "तहसील बकानी" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

ड. क्रम संख्यांक 29 के सामने, स्तम्भ संख्यांक 5 में, विद्यमान अभियंतक "उप तहसील रावला", के स्थान पर अभियंतक "तहसील रावला" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[प.4(2)विल्लःकर/2021-283]
राज्यपाल के आदेश से,

(टीमा झाढ़ि) संयुक्त शासन सचिव
बित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 24, 2021
एस.ओ.466.-रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना संख्याक प.2(17)बित्त/कर/2010/पार्ट-226 दिनांक 02.09.2020 में इसके द्वारा लिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन
उक्त अधिसूचना की सारणी में,-
क. स्तम्भ संख्यांक 3 और 4 में, क्रम संख्यांक 5 के सामने, विद्यमान अभिव्यक्ति
\[ (xvii) \text{नायब तहसीलदार, कल्याणपुर कल्याणपुर} \]
के पश्चात् अभिव्यक्ति
\[ (xviii) \text{तहसीलदार, धनाऊ धनाऊ} \]
जोड़ी जायेगी;
ख. स्तम्भ संख्यांक 3 में,-
(i) क्रम संख्यांक 8 के सामने, विद्यमान अभिव्यक्ति "(iv) नायब तहसीलदार, बन्जू", के स्थान पर अभिव्यक्ति "(iv) तहसीलदार, बन्जू" प्रतिस्थापित की जायेगी; और
(ii) क्रम संख्यांक 12 के सामने, विद्यमान अभिव्यक्ति "(x) नायब तहसीलदार, मण्डावर", के स्थान पर अभिव्यक्ति "(x) तहसीलदार, मण्डावर" प्रतिस्थापित की जायेगी;
ग. विद्यमान क्रम संख्यांक 16 और उसकी प्रतिष्ठियों के स्थान पर लिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

<table>
<thead>
<tr>
<th>संख्या</th>
<th>जयपुर</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>16.</td>
<td>(i) उप-रजिस्ट्रार, जयपुर-प्रथम</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(ii) उप-रजिस्ट्रार, जयपुर-द्वितीय</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(iii) उप-रजिस्ट्रार, जयपुर-तृतीय</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(iv) उप-रजिस्ट्रार, जयपुर-चतुर्थ</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(v) उप-रजिस्ट्रार, जयपुर-पंचम</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(vi) उप-रजिस्ट्रार, जयपुर-षष्ठम</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(vii) उप-रजिस्ट्रार, जयपुर-सप्तम</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(viii) उप-रजिस्ट्रार, जयपुर-अष्ठम</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(ix) उप-रजिस्ट्रार, जयपुर-नवम</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(x) उप-रजिस्ट्रार, जयपुर-दशम</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(xi) उप-रजिस्ट्रार, सांगानेर-प्रथम</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(xii) उप-रजिस्ट्रार, सांगानेर-द्वितीय</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(xiii) उप-रजिस्ट्रार, आमेर</td>
</tr>
<tr>
<td>(xiv) उप-रजिस्ट्रार, बस्सी</td>
<td>जयपुर उप जिले की बस्सी तहसील का क्षेत्र</td>
</tr>
<tr>
<td>(xv) उप-रजिस्ट्रार, चाकसू</td>
<td>जयपुर उप जिले की चाकसू तहसील का क्षेत्र</td>
</tr>
<tr>
<td>(xvi) उप-रजिस्ट्रार, चौमू</td>
<td>जयपुर उप जिले की चौमू तहसील का क्षेत्र</td>
</tr>
<tr>
<td>(xvii) उप-रजिस्ट्रार, दूल्लू</td>
<td>जयपुर उप जिले की दूल्लू तहसील का क्षेत्र</td>
</tr>
<tr>
<td>(xviii) उप-रजिस्ट्रार, जमवारामढ़</td>
<td>जयपुर उप जिले की जमवारामढ़ तहसील का क्षेत्र</td>
</tr>
<tr>
<td>(xix) उप-रजिस्ट्रार, फागी</td>
<td>जयपुर उप जिले की फागी तहसील का क्षेत्र</td>
</tr>
<tr>
<td>(xx) नायब तहसीलदार, बगर</td>
<td>जयपुर उप जिले की बगर उप तहसील का क्षेत्र</td>
</tr>
<tr>
<td>(xxi) नायब तहसीलदार, मुंडोता</td>
<td>जयपुर उप जिले की मुंडोता उप तहसील का क्षेत्र</td>
</tr>
<tr>
<td>(xxii) नायब तहसीलदार, जालसू</td>
<td>जयपुर उप जिले की जालसू उप तहसील का क्षेत्र</td>
</tr>
<tr>
<td>(xxiii) नायब तहसीलदार, रामपुरा डाबड़ी</td>
<td>जयपुर उप जिले की रामपुरा डाबड़ी उप तहसील का क्षेत्र</td>
</tr>
<tr>
<td>(xxiv) नायब तहसीलदार, गोविन्दगढ़</td>
<td>जयपुर उप जिले की गोविन्दगढ़ उप तहसील का क्षेत्र</td>
</tr>
<tr>
<td>(xxv) नायब तहसीलदार, खेजरीली</td>
<td>जयपुर उप जिले की खेजरीली उप तहसील का क्षेत्र</td>
</tr>
<tr>
<td>(xxvi) तहसीलदार, विराटनगर</td>
<td>विराटनगर</td>
</tr>
<tr>
<td>(xxvii) तहसीलदार, मौजमबाद</td>
<td>मौजमबाद</td>
</tr>
<tr>
<td>(xxviii) तहसीलदार, विशेषनगढ़ रेनवाल</td>
<td>विशेषनगढ़ रेनवाल</td>
</tr>
<tr>
<td>(xxix) तहसीलदार, कोटखावंडा</td>
<td>कोटखावंडा</td>
</tr>
<tr>
<td>(xxx) उप-रजिस्ट्रार, कोटपुतली</td>
<td>कोटपुतली</td>
</tr>
<tr>
<td>(xxxi) उप-रजिस्ट्रार, सांभर</td>
<td>सांभर</td>
</tr>
<tr>
<td>(xxxii) उप-रजिस्ट्रार, शहपुरा</td>
<td>शहपुरा</td>
</tr>
<tr>
<td>(xxxiii) उप-रजिस्ट्रार, माौधराजपुरा</td>
<td>माौधराजपुरा</td>
</tr>
<tr>
<td>(xxxiv) नायब तहसीलदार, आंधी</td>
<td>आंधी</td>
</tr>
<tr>
<td>(xxxv) नायब तहसीलदार, तुंगा</td>
<td>तुंगा</td>
</tr>
<tr>
<td>(xxxvi) नायब तहसीलदार, अमरसर</td>
<td>अमरसर</td>
</tr>
<tr>
<td>(xxxvii) नायब तहसीलदार, मनोहरपुर</td>
<td>मनोहरपुर</td>
</tr>
</tbody>
</table>
भाग 4(ग) राजस्थान राज-पत्र, फरवरी 24, 2021

| (xxxviii) तहसीलदार, पावटा | पावटा |
| (xxxix) नायब तहसीलदार, कालवाड | कालवाड |

घ. क्रम संख्यांक 19 के सामने, स्तम्भ संख्यांक 3 में,-
(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "(vii) नायब तहसीलदार, सुनैल" के स्थान पर अभिव्यक्ति "(vii) तहसीलदार, सुनैल" प्रतिस्थापित की जायेगी; और
(ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "(x) नायब तहसीलदार, बकानी" के स्थान पर अभिव्यक्ति "(x) तहसीलदार, बकानी" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

ड. क्रम संख्यांक 29 के सामने, स्तम्भ संख्यांक 3 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "(xix) नायब तहसीलदार, रावला", के स्थान पर अभिव्यक्ति "(xix) तहसीलदार, रावला" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[प.4(2)वित्त/कर/2021-284]
राज्यपाल के आदेश से,

(टीना डाबी)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 24, 2021

एस.ओ.467.-रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 69 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान रजिस्ट्रीकरण नियम, 1955 को और संशोधित करने के लिए महानिरीक्षक रजिस्ट्रीकरण, राजस्थान द्वारा बनाये गये निम्नलिखित नियमों को, उक्त अधिनियम की धारा 69 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा अनुमोदित और प्रकाशित करती है, अथवात  :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2021 है।
(2) ये तुरंत प्रवृत होंगे।

2. नियम 79 का संशोधन.- राजस्थान रजिस्ट्रीकरण नियम, 1955 के खंड-II के विद्यमान नियम 79 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्  :-

"79. कीस का प्रतिदान.- (1) रजिस्ट्रीकरण से इंकार किये जाने, या अन्य कारणों से रजिस्ट्रीकरण न होने की स्थिति में, कमीशन, समन, हाजिरी और यात्रा भर्तियों के लिए उद्गृहीत कीस, जहां ऐसी कीस अर्जित हो गयी है, उसे छोड़कर, कोई कीस जो उद्गृहीत कर ली गयी हो, वह प्रतिदाता कर दी जायेगी।
(2) निरीक्षण या तलाशी कीस उन मामलों में प्रतिदाता की आ सकेगी जहां कोई निरीक्षण या तलाशी नहीं की गयी हो किन्तु उन मामलों में प्रतिदाता नहीं की जायेगी जहां आंशिक निरीक्षण या तलाशी कर ली गयी हो।
(3) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उस फीस से अधिक प्रभावित कोई रजिस्ट्रीकरण फीस, जो वस्तुतः नियमों के अंतर्गत प्रभाव है, कलक्टर (स्टाम्प) के विवेक से, प्रतिदिन की जा सकने वाले कानून का लिए दावा छोड़ मास के भीतर किया गया हो और कलक्टर (स्टाम्प) का समाधान हो गया हो कि स्पष्ट या फीस अधिक प्रभावित हुई है।

(4) फीस के प्रतिदिन के लिए लिखित आदेश कलक्टर (स्टाम्प) को किया जायेगा जो उस पर आदेश पारित करेगा। कलक्टर (स्टाम्प) यह देखने के लिए उत्तरदायी होगा कि प्रतिदिन की जाने वाली फीस की पूरी रकम की रसीद और अभिलिखित कर ली गयी है।

[प.4.(2)वित्त/कर/2021-285]
राज्यपाल के आदेश से,

(टीना दाबी)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 24, 2021

एस.ओ. 468.-रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 78 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक न.4.(3)वित्त/कर/2017-123 दिनांक 08.03.2017 को अंतिमित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर जो लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि भागीदारी फार्म, प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी या अमूल्येदार फार्म लिमिटेड कम्पनी के सीमित दायित्व भागीदारी में या विपर्येन संपरिवर्तन से संबंधित लिखित पर दस हजार रुपये से अधिक प्रभाव रजिस्ट्रीकरण फीस का परिहार किया जायेगा।

[प.4.(2)वित्त/कर/2021-286]
राज्यपाल के आदेश से,

(टीना दाबी)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 24, 2021

एस.ओ. 469.-राजस्थान वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम सं. 9) के अध्याय 4 की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, लोकहित में ऐसा किया जाना
समीचीन समझने पर, इसके द्वारा आदेश देती है कि जहां भूमि कर की बकाया 30.06.2021 तक जमा कर दी जाती है, भूमि कर पर संदेय व्याज और शास्त्र का परिहार किया जायेगा।

[प.4(2)विवत्क/कर/2021-287]
राज्यपाल के आदेश से,

(टीना डबो)
संयुक्त शासन सचिव

परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 24, 2021

एस.ओ.470.-राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, 01.04.2021 को और उसके पश्चात क्रय किये गये और 31.03.2022 तक रजिस्ट्रीकृत और ग्रामीण मागूं तथा अन्य मागूं (राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के उपबंधों के अधीन यथा-यथागृह) पर अनन्य रूप से चलाये जाने वाले नये मंजिली यात्री यानों को उनके रजिस्ट्रीकरण की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन संदेय मोटर यान कर के संदाय से, इसके द्वारा छूट देती है।

[प.6(179)परि/कर/मु./2021-22/1]
राज्यपाल के आदेश से,

(महेन्द्र कुमार खींची)
संयुक्त शासन सचिव

परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 24, 2021

एस.ओ.471.-राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा,-
(i) नष्ट हो चुके यानों पर संदेय मोटर यान कर, विशेष सड़क कर, अधिभास, शास्त्र और व्याज, यदि कोई हो, के संदाय से छूट देती है यदि यान के नष्ट होने की तारीख तक का संदेय मोटर यान कर, विशेष सड़क कर और अधिभास दिनांक 31.03.2021 को या उससे पूर्व निश्चित करा दिया जाता है;
राजस्थान राज-पत्र, फरवरी 24, 2021  
भाग 4(ग)

(ii) नष्ट को चुके यानों से भिन्न यानों पर 31.01.2021 तक मोटर यान कर, विशेष सड़क कर, एक बारीय कर, एकमुश्त कर और अधिभार पर संदेय शासित और व्याज के संदाय से छूट देती है, यदि,-  
(k) मोटर यान कर, एक बारीय कर और अधिभार पर 31.01.2021 के पश्चात् शौच्य शासित और व्याज, यदि कोई हो, 31.03.2021 को या उससे पूर्व निषिद्ध करा दिया जाता है; और  
(ख) कोई शौच्य मोटर यान कर, विशेष सड़क कर, एक बारीय कर, एकमुश्त कर और अधिभार 31.03.2021 को या उससे पूर्व निषिद्ध करा दिया जाता है; और  
(iii) राज्य के बाहर रजिस्ट्रीकृत और तीस दिन से अधिक के उपयोग के लिए राज्य में लाये गये  
 गैर-परिवहन यानों पर 31.01.2021 तक एक बारीय कर और अधिभार पर संदेय शासित और  
 व्याज के संदाय से छूट देती है, यदि 31.01.2021 तक शौच्य एक बारीय कर और अधिभार 31.03.2021 को या उससे पूर्व निषिद्ध करा दिया जाता है।  
उपर्युक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अध्योपी देनी होगी, अथवा:-  
(i) यान का स्वामी छूट के लिए कराधान अधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकेगा।  
(ii) कराधान अधिकारी कर की संगणना करेगा और मांग नोटिस जारी करेगा।  
(iii) नष्ट हो चुके यानों का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा रद्द किया जायेगा।  
(iv) अधिभार, शासित या व्याज, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए मोटर यान कर, विशेष  
 सड़क कर की पूर्व में संदृष्ट रकम का प्रतिदिन नहीं किया जायेगा।  
(v) यदि छूट के संबंध में कोई विवाद प्रदूषक होता है तो परिवहन आयुक्त का विनिमित्र अंतिम  
 होगा।  
स्पष्टीकरण: यान के नष्ट होने की तारीख परिवहन आयुक्त द्वारा विनिमित्र प्रक्रिया के अनुसार  
अधिधारित की जायेगी।  

[प.6(179)परिकर/मु./2021-22/2]  
राज्यपाल के आदेश से,  
(महेन्द्र कुमार खींची)  
संयुक्त शासन सचिव  
परिवहन विभाग  
अधिसूचना  
जयपुर, फरवरी 24, 2021  
एस.ओ.472-राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की  
धारा 3 के साथ पदला धारा 4 के उप-धारा (1) के खण्ड (क) और खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों  
का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इस विभाग की, समय-समय पर यथासंशोधित, अधिसूचना
संख्यांक प.6(179)परिक्रमा./2019-20/3 दिनांक 10.07.2019 में इसके द्वारा, दिनांक 01.04.2021 से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,

(i) सारणी के क्रम संख्यांक 2 के सामने, स्तंभ 2 की विद्यमान मद (ख) और उससे संबंधित स्तंभ 2 और स्तंभ 3 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

<table>
<thead>
<tr>
<th>(ख) अन्य मार्ग</th>
</tr>
</thead>
</table>
| (i) प्रतिदिन 100 कि.मी. तक चलने वाली भाग | प्रति माह ₹ 230/- प्रति सीट  
| (ii) प्रतिदिन 100 कि.मी. से अधिक और 150 कि.मी. तक चलने वाली भाग | प्रति माह ₹ 250/- प्रति सीट  
| (iii) प्रतिदिन 150 कि.मी. से अधिक और 200 कि.मी. तक चलने वाली भाग | प्रति माह ₹ 280/- प्रति सीट  
| (iv) प्रतिदिन 200 कि.मी. से अधिक और 250 कि.मी. तक चलने वाली भाग | प्रति माह ₹ 300/- प्रति सीट  
| (v) प्रतिदिन 250 कि.मी. से अधिक और 300 कि.मी. तक चलने वाली भाग | प्रति माह ₹ 320/- प्रति सीट  
| (vi) प्रतिदिन 300 कि.मी. से अधिक और 350 कि.मी. तक चलने वाली भाग | प्रति माह ₹ 520/- प्रति सीट  
| (vii) प्रतिदिन 350 कि.मी. से अधिक और 400 कि.मी. तक चलने वाली भाग | प्रति माह ₹ 540/- प्रति सीट  
| (viii) प्रतिदिन 400 कि.मी. से अधिक चलने वाली भाग | प्रति माह ₹ 560/- प्रति सीट  

(ii) सारणी के क्रम संख्यांक 7 के सामने, स्तंभ 2 की विद्यमान मद (क) और उससे संबंधित स्तंभ 2 और स्तंभ 3 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

<table>
<thead>
<tr>
<th>(क) गैर-अस्थायी परिस्थितियों पर चलने वाले तीन लोगों से अधिक वाले मोटर यान</th>
</tr>
</thead>
</table>
| (i) 22 से अधिक और 32 तक की बैठक क्षमता के साथ भाग | प्रति माह ₹ 700/- प्रति सीट  
| (ii) 32 से अधिक की बैठक क्षमता के साथ भाग | अधिकतम ₹ 40,000/- प्रति माह के अध्यधीन रहते हुए प्रति माह ₹ 700/- प्रति सीट  
| (iii) स्लीपर बस | अधिकतम ₹ 40,000/- प्रति माह के अध्यधीन रहते हुए ₹
(iii) परन्तु में:-

(क) विद्युमान खण्ड (iii) के पश्चात् और विद्युमान खण्ड (iv) से पूर्व, निम्नलिखित नया खण्ड (iii-k) अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(iii-k) क्रम संख्यांक 7 के सामने स्तंभ 2 में खण्ड (क) के उप-खण्ड (i) और (ii) के अन्तर्गत आने वाले और अन्य रूप से राजस्व खण्ड की सीमाओं के भीतर चलने वाले मोटर यान के मामले में कर, ऐसे मोटर यान पर संदेय कर का 50 प्रतिशत होगा;"; और

(ख) विद्युमान खण्ड (viii) के पश्चात् और विद्युमान टिप्पण से पूर्व, निम्नलिखित नया खण्ड (ix) अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(ix) 01.03.2021 को या उसके पश्चात् प्रथम बार रजिस्ट्रीकृत यात्री यान पर क्रम संख्यांक 13 के सामने स्तंभ 3 में यथा विनिर्दिष्ट संदेय कर से छूट होगी, यदि यान रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 15 दिन के भीतर गैर-अस्थायी परिमित के अन्तर्गत आ जाये।"

[प.6(179)परि/कर/मू. /2021-22/3डी]
राज्यपाल के आदेश से,

(महेन्द्र कुमार खींची)
संयुक्त शासन सचिव

परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 24, 2021

एस.ओ.473.-राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (क), खण्ड (ग) और खण्ड (गग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.6(179)परि/कर/मू. / 2019-20/4 दिनांक 10.07.2019 में इसके दृश्या, दिनांक 01.04.2021 से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की सारणी में, स्तंभ 2 में क्रम संख्यांक 1 के सामने विद्युमान मद (ख) और स्तंभ 2 और 3 में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"  (ख) उपरोक्त प्रवर्तन के अन्तर्गत नहीं आने वाले कोई अन्य परिवहन यान या यान जैसे कि ड्रम्पर, लोडर, कैम्पर बैन, ट्रेलर, टिप्पर, कैशवैन, अधिकतम र. 35000/- के अधिक रहे हुए, र. 1800 प्रति 1000 किलोग्राम। "
भाग 4(ग)  राजस्थान राज-पत्र, फरवरी 24, 2021  888

| मोबाइल कॉटीन, हॉलपैक डिपर, मोबाइल कंटेनर, एम्बुलेंस, एनीमल एम्बुलेंस, फायर टेंस, स्टोकेड लैडसे, आंकिजरी टेंस, और फायर फाइटिंग यान, हीयरसेज, मेट कैरियर, मोबाइल बिलिनक, एक्स-रे वैन, लाइफ्सेरी वैन इत्यादि जिनका जी.वी.डब्ल्यू. 16500 कि.ग्र. से अधिक हो। | जी.वी.डब्ल्यू. या उसके भाग के लिए प्रतिवर्ष  |

[प.6(179)पर/कर/मू.2021-22/4ए]
राज्यपाल के आदेश से,

(महेन्द्र कुमार कीवी)
संयुक्त शासन सचिव

परिवहन विभाग
अधिशस्त्र
जयपुर, फरवरी 24, 2021

एस.ओ.474.-राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान मोटर यान कराधान नियम, 1951 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान मोटर यान कराधान (संशोधन) नियम, 2021 है।
   (2) ये तुरंत प्रवृत होंगे।

2. नियम 25 का संशोधन.- राजस्थान मोटर यान कराधान नियम, 1951, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्देशित किया गया है, के नियम 25 के विद्यमान उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-
   "(2) अभ्यारण या उपयोग में न लाने की कालावधि मंजिली गाड़ियों के लिए सात दिन से कम और मंजिली गाड़ियों से भिन्न के लिए तीस दिन से कम की नहीं होगी। ऐसे अभ्यारण की कालावधि, यान के चोरी हो जाने की दशा में के सिवाय, यानों के समस्त प्रवर्गों के लिए नव्वे दिन से अधिक की नहीं होगी।"

3. नियम 41 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 41 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "ड्राइवर की सीट अपवर्जित की जायेगी" के स्थान पर अभिव्यक्ति "ड्राइवर और कण्डक्टर की सीट अपवर्जित की जायेगी" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[प.6(179)पर/कर/मू.2021-22/4ए]
राज्यपाल के आदेश से,

(महेन्द्र कुमार कीवी)
संयुक्त शासन सचिव
राजस्थान राज-पत्र, फरवरी 24, 2021
भाग 4(ग)

परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 24, 2021

एस.ओ.475.-राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा दो पहिया गैर-परिवहन यानों और दस तक की बैठक क्षमता वाले चार पहिया गैर-परिवहन यानों के स्वामित्व के अन्तरण के समय पर संदेह अतिरिक्त एकबारी कर के 50 प्रतिशत के संदाय से तुरंत प्रभाव से छूट देती है।

यह अधिसूचना 31.03.2022 तक प्रौद्यत रहेगी।

[प.6(179)परि/कर/मु./2021-22/6]
राज्यपाल के आदेश से,

(महेंद्र कुमार खींची)
संयुक्त शासन सचिव

परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 24, 2021

एस.ओ.476.-मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 200 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इसके अनुसरण में जारी अधिसूचना सं. प.7(47)परिनियम/मु./87/पार्ट/12409 दिनांक 08.07.2020 को अतिरिक्त करते हुए राज्य सरकार, नीचे दी गयी अनुसूची के स्तम्भ संख्यांक 2 और 3 में वर्णित, उक्त अधिनियम की धाराओं के अधीन कार्य और दण्डनीय अपराधों के शमन के लिए, उनके प्रत्येक के साथन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ संख्यांक 4 में विनिर्दिष्ट रक्षम के लिए, निम्नलिखित अधिकारियों को इसके द्वारा प्राधिकृत करती हैं:-

(1) संपूर्ण राज्य में, परिवहन विभाग के अधिकारी जो मोटर यान उप-निरीक्षक की रैंक से नीचे के न हों;
(2) जयपुर और जोधपुर आयुक्तलाय क्षेत्रों में यातायात पुलिस और पुलिस के अधिकारी जो हैड-कांस्टेबल की रैंक से नीचे के न हों;
(3) जयपुर और जोधपुर आयुक्तलाय क्षेत्रों के सिवाय, राज्य के शेष भाग में उनके क्रमिक क्षेत्रों में यातायात पुलिस और पुलिस के अधिकारी जो सहायक उप-निरीक्षक की रैंक से नीचे के न हों;
और
(4) संपूर्ण राज्य में, मोबाइल यातायात इकाइयों से संलग्न अधिकारी जो हैड-कांस्टेबल की रैंक से नीचे के न हों.
परन्तु पुलिस और यातायात पुलिस के अधिकारी धारा 182क की उप-धारा (1), धारा 182क की उप-धारा (3), धारा 182क की उप-धारा (4), धारा 182ख, धारा 192क, धारा 194 की उप-धारा (1) (सप्ततिथ धारा 113, 114), धारा 194 की उप-धारा (1क) और धारा 194 की उप-धारा (2) के अधीन कारित और दण्डनीय अपराधों के शमन के लिए प्राधिकृत नहीं होंगे।

अनुसूची

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र. सं.</th>
<th>धाराएं जिनके अधीन कारित अपराध का शमन किया जाना है</th>
<th>अपराध</th>
<th>रकम जिसके लिए अपराध का शमन किया जाना है (rupaye में)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>177 अपराध के दण्ड के लिए साधारण उपबंध</td>
<td>प्रथम अपराध के लिए- (i) दो पहिया/ई-रिक्शा/तीन पहिया के लिए 100/- (ii) उपयुक्त से भिन्न 200/- पश्चात्तरी अपराध के लिए- (i) दो पहिया/ई-रिक्शा/तीन पहिया के लिए 200/- (ii) उपयुक्त से भिन्न 400/-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>178(1) मंजिली गाड़ी में टिकट या पास के बिना यात्रा करना</td>
<td>100/-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>178(2) मंजिली गाड़ी के कंप्यूटर द्वारा कर्त्तव्य की अवहेलना</td>
<td>500/-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>178(3)(क) दो पहिया या तीन पहिया ठेका गाड़ी के ड्राईवर द्वारा गाड़ी चलाने या यात्रियों को ले जाने से इंकार करना</td>
<td>50/-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>178(3)(ख) दो पहिया या तीन पहिया ठेका गाड़ी से भिन्न ठेका गाड़ी के ड्राईवर द्वारा गाड़ी चलाने या यात्रियों को ले जाने से इंकार करना</td>
<td>200/-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>179(1) ड्राईवर से किसी निर्देश की अवजा या किसी कृत्य के निर्विहर्त में बाधा डालना</td>
<td>500/-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>179(2) जानकारी देने से इंकार करना या मिलेया जानकारी देना।</td>
<td>1000/-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>नं.</td>
<td>अधिनियम का विभाग</td>
<td>यान के उपर अनुरक्त के लिए की अनुज्ञा की आवेदन करने के लिए विधि</td>
<td>मानदंड</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>------------------</td>
<td>-------------------------------------------------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>8.</td>
<td>180</td>
<td>अप्राधिक सूत्रित व्यक्ति को यान चलाने की अनुज्ञा देना</td>
<td>5000/-</td>
</tr>
<tr>
<td>9.</td>
<td>181</td>
<td>विधिवादन अनुरक्त के बिना यान चलाना</td>
<td>5000/-</td>
</tr>
<tr>
<td>10.</td>
<td>182(1)</td>
<td>अधिनियम के अधीन निर्देशित के पश्चात् सार्वजनिक स्थान में मोटर यान चलाना या पहले से धारित चालन-अनुरक्ति पर किए गए पृष्ठांक को प्रकट किए बिना अनुरक्ति के लिए आवेदन करना या इसे अभिप्राप्त करना</td>
<td>10000/-</td>
</tr>
<tr>
<td>11.</td>
<td>182(2)</td>
<td>अधिनियम के अधीन निर्देशित के पश्चात् सार्वजनिक स्थान पर मंजिला गाड़ी के कण्डकट के रूप में कार्य करना या पहले से धारित कण्डकट अनुरक्ति पर किए गए पृष्ठांक को प्रकट किए बिना नई कण्डकट अनुरक्ति के लिए आवेदन करना या इसे अभिप्राप्त करना</td>
<td>1000/-</td>
</tr>
<tr>
<td>12.</td>
<td>182(1)</td>
<td>व्यवहारी, वित्तीयता या आयातकर्ता द्वारा अधिन 7 या उसके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों का उल्लंघन कर मोटर यानों के विक्रय या परिवर्तन करने संबंधी अपराध</td>
<td>प्रति ऐसे यान के लिए 1,00,000/-</td>
</tr>
<tr>
<td>13.</td>
<td>182(3)</td>
<td>नागुक सुरक्षा संघटन, जो अधिन 7 या उसके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों का अनुपालन नहीं करता है, का विक्रय करने संबंधी अपराध</td>
<td>प्रति ऐसे संघटन के लिए 1,00,000/-</td>
</tr>
<tr>
<td>14.</td>
<td>182(4)</td>
<td>मोटर यान स्वामी द्वारा यान में परिवर्तन जो अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों में अनुज्ञात न हो</td>
<td>प्रति ऐसे परिवर्तन के लिए 5000/-</td>
</tr>
<tr>
<td>15.</td>
<td>182</td>
<td>धारा 62क के उल्लंघन के लिए दण्ड (आकार से बड़े यानों के रजिस्ट्रीकरण)</td>
<td>5000/-</td>
</tr>
<tr>
<td>नं.</td>
<td>अवधारणा</td>
<td>विवरण</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>-----------</td>
<td>---------</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
| 16. | 183(1)(i) | अत्यधिक गति से हल्का मोटर यान चलाना या किसी अन्य व्यक्ति से चलवाना | प्रथम अपराध के लिए-1000/-
|     |           | इस उप-धारा के अधीन द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसे हाइड्रेवर की चालन-अनुज्ञित धारा 206(4) के उपबंधों के अनुसार परिवर्तन करना |
| 17. | 183(1)(ii) | अत्यधिक गति से मध्यम या भारी माल या यात्री यान चलाना या किसी अन्य व्यक्ति से चलवाना | प्रथम अपराध के लिए-2000/-
|     |           | इस उप-धारा के अधीन द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसे हाइड्रेवर की चालन-अनुज्ञित धारा 206(4) के उपबंधों के अनुसार परिवर्तन करना |
| 18. | 184(७)  | खतरनाक तरीके से यान चलाना (हाथ में रखी संसूचना युक्तियों के प्रयोग की सीमा तक) | प्रथम अपराध के लिए-1000/-
|     |           | पश्चातवर्ती अपराध के लिए-10000/- |
| 19. | 186      | यान चलाने के लिए मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य होते हुए भी यान चलाना | प्रथम अपराध के लिए-500/-
|     |           | पश्चातवर्ती अपराध के लिए-1000/- |
| 20. | 189      | राज्य सरकार की स्वीकृत सहमति के बिना किसी दो पिहारा या गति के मुकाबले में भाग लेना | प्रथम अपराध के लिए-5000/-
|     |           | पश्चातवर्ती अपराध के लिए-10000/- |
| 21. | 190(२)  | किसी सार्वजनिक स्थान में कोई मोटर यान ऐसे यान या चलवाना या चलने देना जिससे सड़क सुरक्षा, शोर नियंत्रण और वायु प्रदूषण के संबंध में विहित मानकों का उल्लंघन होता हो | प्रथम अपराध के लिए-
|     |           | (i) दो पहिया/ई-रिक्शा/तीन पहिया मोटर यान के लिए 500/-
|     |           | (ii) दो पहिया और तीन पहिया गैर-परिवहन यान से भिन्न गैर-परिवहन यान के लिए 1000/-
|     |           | (iii) हल्का परिवहन मोटर यान (दो पहिया/ई-रिक्शा/तीन पहिया परिवहन मोटर यान से भिन्न) के लिए 1500/-
|     |           | (iv) मध्यम/भारी परिवहन यान के लिए 2000/-
|     |           | पश्चातवर्ती अपराध के लिए-
|     |           | (i) दो पहिया/ई-रिक्शा/तीन पहिया मोटर यान के लिए 1000/-
|     |           | (ii) दो पहिया और तीन पहिया गैर-
राजस्थान राज-पत्र, फरवरी 24, 2021
भाग 4(ग)

| 22. 192 | रजिस्ट्रीकरण या यान के ठीक हालत में न होने के प्रमाणपत्र के बिना यान का उपयोग:--
| (i) दो पहिया या तीन पहिया मोटर यान (ii) दो पहिया या तीन पहिया मोटर यान से भिन्न यात्री यान (iii) कृष्ण ट्रेक्टर/ट्रेलर | प्रथम अपराध के लिए -2000/- पश्चात्तरी अपराध के लिए -5000/- प्रथम अपराध के लिए -2000/- पश्चात्तरी अपराध के लिए -5000/-
| (iv) माल यान | प्रथम अपराध के लिए -5000/- पश्चात्तरी अपराध के लिए -10000/-

| 23. 192 के परमिट के बिना या परमिट शर्तों के उल्लंघन में यान का उपयोग | परमिट के दायित्व व तत्त्वकर्ता के इलाज के लिए हलचल यान/मध्यम मोटर यान के लिए 10000/- डो पहिया/तीन पहिया और अन्य रूप से नगरीय भारी मार्ग पर चलने वाली मंजिली गाड़ी बस के लिए 2000/-

| 24. 194(1) | (i) धारा 113, 114 के उल्लंघन में अनुज्ञेय भार से अधिक भार वाले | लदान सीमा से अधिक भार को उतरवाने के लिए प्रभारों का संदेख करने के दायित्व सहित ऐसे अधिक भार के लिए 5000/- और प्रति टन अधिक भार के लिए 1000/- अतिरिक्त 5000/-
| (ii) धारा 115 के उल्लंघन में (प्रतिष्ठान/निर्वाचित क्षेत्र में) यान को चलाना |

<p>| 25. 194(1क) | ऐसा मोटर यान चलाना जिसमें उसकी परिमापगत सीमाओं से बहिर्गत बनने हो | ऐसे भार को उतरवाने के लिए संदेख प्रभारों के दायित्व सहित 5000/- |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>संख्या</th>
<th>नाम</th>
<th>विवरण</th>
<th>इम्टियाज़</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>26.</td>
<td>194(2)</td>
<td>प्राधिकारी द्वारा निदेश दिये जाने के पश्चात यान को रोकने और भार कराने से इंकार करना</td>
<td>10000/-</td>
</tr>
<tr>
<td>27.</td>
<td>194क</td>
<td>परिवहन यान में क्षमता से अधिक यात्री वहन करना</td>
<td>प्रति अधिक सवारी 200/-</td>
</tr>
<tr>
<td>28.</td>
<td>194ख(1)</td>
<td>सीट बैंल के बिना ड्राईवर या यात्री</td>
<td>1000/-</td>
</tr>
<tr>
<td>29.</td>
<td>194ख(2)</td>
<td>सुरक्षा बैंल/बाल अवरोध प्रणाली के बिना 14 वर्ष से कम आयु के बालक को ले जाना</td>
<td>500/-</td>
</tr>
<tr>
<td>30.</td>
<td>194ग</td>
<td>दो पहिया यान पर दो व्यक्तियों से अधिक सवारी</td>
<td>100/-</td>
</tr>
<tr>
<td>31.</td>
<td>194घ</td>
<td>ड्राईवर और सवारी द्वारा हेलमेट के बिना सवारी</td>
<td>1000/-</td>
</tr>
<tr>
<td>32.</td>
<td>194ङ</td>
<td>आपत्तिकालीन यानों को अध्ययन से न गुजरने देना (अन्तिम सेवा और एन्जुलेस)</td>
<td>1000/-</td>
</tr>
<tr>
<td>33.</td>
<td>194च(क)</td>
<td>1. अनावश्यक रूप से या निरन्तर हॉम बजाना 2. प्रतिष्ठित क्षेत्रों में हॉम बजाना</td>
<td>दो पहियातीन पहिया के लिए 500/- उपर्युक्त से भिन्न के लिए 1000/-</td>
</tr>
<tr>
<td>34.</td>
<td>194च(ख)</td>
<td>निशेष गैसों को अवरोध से भिन्न किसी माध्यम से छोड़ना</td>
<td>दो पहिया/तीन पहिया के लिए 500/- उपर्युक्त से भिन्न के लिए 1000/-</td>
</tr>
<tr>
<td>35.</td>
<td>196</td>
<td>अवैधक उद्देश्य के लिए चलाना</td>
<td>दो पहिया/तीन पहिया के लिए 1000/- उपर्युक्त से भिन्न के लिए 2000/-</td>
</tr>
<tr>
<td>36.</td>
<td>198</td>
<td>यान के साथ अनधिकृत हस्तक्षेप</td>
<td>1000/-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

[प.7(47)परिनिर्देश/मु.87/पार्ट/1/1]  
राज्यपाल के आदेश से，

(महेंद्र कुमार खींची)  
संयुक्त शासन सचिव  

परिवहन विभाग  
अधिसूचना  
जयपुर, फरवरी 24, 2021  

एस.ओ.477.-मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केंद्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 200 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, खान विभाग के ई-रवन्द्र के
माध्यम से प्राप्त सूचना के आधार पर 31.01.2021 को या उससे पूर्व उक्त अधिनियम की धारा 113 की उप-धारा (3) के खंड (ख) के अधीन कारित अपराधों का शमन करने के लिए, नीचे दी गयी सारणी के स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट रकम के अध्यधीन रहते हुए उक्त सारणी के स्तंभ 3 में यथाविनिर्दिष्ट शमन रकम के लिए, इसके संबंध में जिला परिवहन अधिकारी को प्राधिकृत करती है।

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र. सं.</th>
<th>इस विभाग की अधिसूचना सं.</th>
<th>शमन रकम (इस विभाग की अधिसूचना सं.</th>
<th>न्यूनतम संदेय शमन रकम (र. में)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>प.7(47)परिनियम/मु./पार्ट/12409</td>
<td>प.7(47)परिनियम/मु./पार्ट/12409</td>
<td>पाटर्स/87/पार्ट/1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>दिनांक 08.07.2020 के आधार पर</td>
<td>दिनांक 08.07.2020 के आधार पर</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>31.01.2021 तक यान के लिए संदेय कुल शमन रकम (र. में)</td>
<td>31.01.2021 तक यान के लिए संदेय रकम का प्रतिशत)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. 1 लाख तक</td>
<td>25 प्रतिशत</td>
<td>5500/-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2. 1 लाख से अधिक और 10 लाख तक</td>
<td>10 प्रतिशत</td>
<td>25000/-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3. 10 लाख से अधिक और 25 लाख तक</td>
<td>8 प्रतिशत</td>
<td>115000/-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4. 25 लाख से अधिक और 50 लाख तक</td>
<td>6 प्रतिशत</td>
<td>235000/-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5. 50 लाख से अधिक और 75 लाख तक</td>
<td>4 प्रतिशत</td>
<td>385000/-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6. 75 लाख से अधिक और 1 करोड़ तक</td>
<td>2 प्रतिशत</td>
<td>485000/-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7. 1 करोड़ से अधिक</td>
<td>1 प्रतिशत</td>
<td>535000/-</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

यह अधिसूचना 31.03.2021 तक प्रकृति रहेगी।

[प.7(47)परिनियम/मु./87/पार्ट/1/2]
राज्यपाल के आदेश से,

(महेंद्र कुमार खींची)
संयुक्त शासन सचिव
FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

Jaipur, February 24, 2021

In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorize the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Finance Department, Tax Division Notification No. F.12(29)FD/Tax/2021-269 to 271, No.F.4(2)FD/Tax/2021-272 to 287 and Transport Department Notification No.F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/2020-21/1, 2, 3D, 4A, 5, 6, F.7(47)/Pari/Rules/H.Q./87/Part/1/1 and F.7(47)/Pari/Rules/H.Q./87/Part/1/2 dated February 24, 2021.

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION

Jaipur, February 24, 2021

S.O. 451. In exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 174 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 9 of 2017), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby notifies the following “Amnesty Scheme-2021” for rebate of tax and settlement of outstanding demands and disputes, hereinafter referred to as the scheme, namely:-

1. Short title and operative period.- (1) This scheme may be called the Amnesty Scheme-2021.

(2) The scheme shall come into force with immediate effect and shall remain in force upto 30.09.2021.

2. Application.- The scheme shall be applicable to all dealers or persons having outstanding demand or dispute under any Act in respect of period upto 30.06.2017, except outstanding demand or dispute in respect of goods included in the Entry 54 of the State List of the Seventh Schedule to the Constitution.

3. Definitions.- (1) In this scheme, unless the subject or context otherwise requires,-

(a) “Act” means any of the following Acts:-

(i) The Rajasthan Sales Tax Act, 1954 (Act No. 29 of 1954);
(ii) The Rajasthan Sales Tax Act, 1994 (Act No. 22 of 1995);
(iii) The Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act No. 74 of 1956);
(iv) The Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003);
(v)The Rajasthan Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 1999 (Act No. 13 of 1999);
(vi) The Rajasthan Tax on Entry of Motor Vehicles into Local Areas Act, 1988 (Act No. 14 of 1988);
(vii) The Rajasthan Entertainments and Advertisements Tax Act, 1957 (Act No. 24 of 1957);
(viii) The Rajasthan Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Act, 1990 (Act No. 9 of 1996); and
The Rajasthan Tax on Luxuries (Tobacco and its Products) Act, 1994 (Act No. 11 of 1994);

(b) “Admitted Tax” means any amount which is admitted by the dealer or person in the return furnished, or in writing before any authority;

(c) “Applicant” means any dealer or person who conveys his willingness for availing benefit under the scheme;

(d) “Assessing Authority” means any officer or authority appointed under the Act;

(e) “Dealer” means any dealer as defined under the Act;

(f) “Declaration Form” means the statutory form or certificate prescribed under the Act for sale or purchase of goods at concessional rate of tax or exemption from tax;

(g) “Department” means the Commercial Taxes Department, Rajasthan;

(h) “Difference Tax” means difference between full rate of tax applicable in the State under the Act and concessional rate or exemption which is applicable on submission of declaration form;

(i) “Dispute” means any case pending in respect of any period upto 30.06.2017 under the Act for which,-

(i) a levy of tax, interest, fee or penalty by an authority appointed or prescribed or authorized under the Act is under any dispute; or

(ii) an assessment, re-assessment on any account, or any other order has been made; or

(iii) an appeal, revision, Writ Petition or Special Leave Petition has been filed; or

(iv) a revision proceeding has been initiated before the Commissioner, Commercial Taxes Department; or

(v) a notice or order has been issued intimating the applicant for payment of tax, interest, fee or penalty; or

(vi) a show cause notice has been issued in any proceeding under the Act requiring payment of any tax, interest, fee or penalty; or

(vii) a proceeding for recovery of tax, interest, fee or penalty has been initiated by or is pending before any authority appointed or prescribed or authorised under the Act;

(j) “Disputed Amount”, means any tax, interest, fee or penalty which is in dispute;

(k) “Outstanding Demand” means any demand pertaining to the Act, which is pending in the Demand and Collection Register;

(l) “Phase” means the period for payment of the amount required as per column number 3 of Table-A, as mentioned in the following Table:-

<table>
<thead>
<tr>
<th>S. No.</th>
<th>Phase</th>
<th>Period</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Phase-I</td>
<td>Upto 31.03.2021</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Phase-II</td>
<td>01.04.2021 to 30.06.2021</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Phase-III</td>
<td>01.07.2021 to 30.09.2021</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(m) “Tax” shall include the composition amount or lump sum in lieu of tax and exemption fee; and

(n) “Total Outstanding Demand or Total Disputed Amount” means the sum total of all outstanding demands or disputed amount pertaining to the dealer or person under any Act.
(2) The words and expressions used in this scheme but not defined shall have the same meaning as assigned to them in the Act to which the outstanding demand or dispute pertains.

4. Benefits under the scheme.- The rebate of tax and waiver of interest, penalty or fee shall be to the extent as mentioned in column number 4 of the Table-A given below on fulfilment of conditions as mentioned in column number 3, for the category of outstanding demand or disputed amount as mentioned in column number 2 of the said table and the conditions mentioned in clause 5 of this Scheme:-

Table-A

For Rebate of Tax and/or Waiver of Interest, Penalty and Late Fee

<table>
<thead>
<tr>
<th>S. No.</th>
<th>Category of outstanding Demand or disputed amount</th>
<th>Conditions</th>
<th>Extent of Rebate of Tax and/or Waiver of Interest, Penalty and Late Fee</th>
</tr>
</thead>
</table>
| 1      | Outstanding demand or disputed amount but excluding those covered under serial number 2, 3, 4 and 5 of this table. | (i) **Phase-I:** The applicant has deposited 90% of the amount of tax.  
(ii) **Phase-II:** The applicant has deposited 95% of the amount of tax.  
(iii) **Phase-III:** The applicant has deposited the 100% amount of tax. | Remaining amount of tax, if any, whole amount of interest, penalty and late fee along with interest accrued up to the date of order under the scheme. |
| 2      | Outstanding demand which relates to declaration forms but excluding those covered under serial number 1, 3, 4 and 5 of this table. | (i) **Phase-I:** The applicant has deposited 20% of difference tax.  
(ii) **Phase-II:** The applicant has deposited 25% of difference tax.  
(iii) **Phase-III:** The applicant has deposited 30% of difference tax. | Remaining amount of difference tax, whole amount of interest, penalty and late fee, if any, along with interest accrued up to the date of order under the scheme. |
| 3      | Outstanding demand or disputed amount which relates to rate of tax, classification of goods or interpretation of Act, but excluding those covered under serial number 1, 2, 4 and 5 of this table. | (i) **Phase-I:** The applicant has deposited whole amount of admitted tax, if any, along with 50% of disputed tax.  
(ii) **Phase-II:** The applicant has deposited whole amount of admitted tax, if any, along with 55% of disputed tax.  
(iii) **Phase-III:** The applicant has deposited whole amount of admitted tax, if any, along with 60% of disputed tax. | Remaining amount of disputed tax, whole amount of interest, penalty and late fee, if any, along with interest accrued up to the date of order under the scheme. |
4. Outstanding demand or disputed amount, which relates to:
   (i) evasion or avoidance of tax; or
   (ii) misuse of declaration form(s)/Certificate(s); or
   (iii) unaccounted goods; or
   (iv) Goods/vehicle in transit, but excluding those covered under serial number 1, 2, 3 and 5 of this table.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Phase-I:</th>
<th>Phase-II:</th>
<th>Phase-III:</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>The applicant has deposited the whole amount of tax, along with 20% of the outstanding penalty.</td>
<td>The applicant has deposited the whole amount of tax, along with 25% of the outstanding penalty.</td>
<td>The applicant has deposited the whole amount of tax, along with 30% of the outstanding penalty.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Whole amount of interest and late fee, if any, along with interest accrued up to the date of order under the scheme and remaining amount of penalty.

5. Total outstanding demand or disputed amount which relates exclusively to interest and/or penalty only, and is more than rupees twenty five crore, but excluding those covered under serial number 1, 2, 3 and 4 of this table.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Phase-I:</th>
<th>Phase-II:</th>
<th>Phase-III:</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>The applicant has deposited 40% of interest and/or penalty.</td>
<td>The applicant has deposited 45% of interest and/or penalty.</td>
<td>The applicant has deposited 50% of interest and/or penalty.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Remaining amount of interest and/or penalty along with interest accrued up to the date of order under the scheme.

**Explanation:**

1. Where any dealer conveys his willingness for availing benefit of the scheme during the period of Phase-I, II or III, as the case may be and deposits the required amount within ten days from the day on which the assessing authority conveys the net amount required to be paid under the scheme or before the last date of the respective Phase, whichever is later, he shall be eligible for the benefit available in the Phase in which he had conveyed his willingness. In case, the dealer fails to deposit the net amount in the time specified above, then he shall be eligible for the benefit under the phase in which he deposits the said amount and in case of continuance of default beyond the operative period of the scheme, he shall not be eligible for any benefit under the scheme.

2. Where any amount has been deposited prior to issuance of this scheme against the demand after its creation and if option is being submitted for the balance outstanding demand, the amount already deposited, if not specifically mentioned in the challan, shall be adjusted firstly against the liability of tax, then it shall be adjusted against the liability of interest, penalty and late fee, respectively. However, if any amount has been deposited in compliance of any court order, it shall be adjusted accordingly.

3. Where any dealer or person had applied under Amnesty Scheme-2017, New Voluntary Amnesty Scheme for Entry Tax-2017, Amnesty Scheme for Entry Tax on Motor Vehicles-2017, Amnesty Scheme for Entertainment Tax-2017 or Amnesty Scheme for Luxury Tax-2017 and deposited any amount under the said Scheme(s) but could not avail the benefit under the corresponding scheme for any reason, in such cases, those persons/dealers shall be eligible for benefits under
this Scheme and the amount deposited in pursuance of those Schemes shall be adjusted and admissible for benefit under this Scheme.

(4) Where the demand or disputed amount comprises entirely of interest and/or penalty and/or late fee, in such cases, the amount of tax shall be deemed to have been deposited.

(5) Where the demand or disputed amount pertaining to the period up to 30.06.2017 has already been deposited and demand for interest pertaining to the same is leviable but not levied, in such cases the interest payable along with the interest accrued up to the date of order under the scheme shall be waived to the extent as per Table-A above.

(6) For category of demand or disputed amount where the dealer or person is not required to deposit any amount as per Table-A above, in such cases, he may convey the same to the Assessing Authority. In cases where no intimation is received from the dealer or person, the assessing authority may proceed to dispose the case at his own level.

(7) For demands or disputed amount pertaining to declaration forms, where the forms are not submitted up to 30.06.2021, recovery proceedings shall not be initiated within the operative period of the scheme if the dealer submits a security in the form of bank guarantee equal to the amount required to be deposited in phase-III as per column number 3 against serial number 2 of Table-A above upto 15.07.2021.

(8) Where any application for rectification related to the demand, for which the dealer or person intends to opt under this scheme is pending before the assessing authority concerned, then on intimation in writing from such dealer or person, he shall dispose it within seven days of such intimation or upto the operative period, whichever is earlier.

(9) In cases which are in dispute and for which the demand is not outstanding in the Demand and Collection Register (DCR), the amount of tax, interest, late fee and/or penalty shall be deemed to be as per the original assessment order or notice issued in regard of the said dispute. In such cases, the assessing authority concerned shall withdraw the proceeding, if any, pending before himself or submit an application for withdrawal of the case pending before any Court or Tax Board or Appellate Authority, as the case may be, after deposit of prescribed amount as per Table-A above, within the operative period of this Scheme.

(10) Where any concealment, fraudulent or misrepresentation of facts has been made in the returns or books of accounts by the dealer or person, such cases shall not be covered under serial number 3 of the Table-A above.

5. Conditions.- The benefits of this scheme shall be available on the fulfillment of the following conditions, namely:-

(i) The applicant has deposited the amount required as per column number 3 of the Table-A above within the operative period of this Scheme or as per Explanation (1) above, as the case may be;

(ii) The applicant has submitted an application for withdrawal of case, if any, pending before any Court or Tax Board or Appellate Authority, as the case may be, within the operative period of this Scheme; and

(iii) No refund of any excess payment already made shall be allowed due to rebate of tax and/or waiver under this Scheme.
6. **Procedure for availing benefit.** (1) To avail the benefit under this scheme, the applicant shall electronically convey his willingness on the Commercial Taxes Department’s website www.rajtax.gov.in regarding the same to the concerned Assessing Authority.

(2) Separate intimation of willingness shall be conveyed for demands/ disputes pending under separate Acts as well as before separate Assessing Authorities.

(3) In case of any dealer or person opting for benefits under this scheme, the Assessing Authority shall electronically convey the details of pending demand(s) and disputed amount against the dealer or person along with the payment to be made in pursuance of this scheme and consequent benefits to be accrued.

(4) The detailed procedure and clarification, if any, for availing benefit under this scheme shall be as notified by the Commissioner, Commercial Taxes Department, Rajasthan.

(5) In case of any dispute regarding the categorization of outstanding demand or dispute under serial number 1 to 5 of Table-A, the decision of Commissioner, Commercial Taxes shall be final.

[No.F.12(29)FD/Tax/2021-269]

By order of the Governor,

(Tina Dabi)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 24, 2021

S.O.452.-In exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 174 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 9 of 2017), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Value Added Tax Rules, 2006, namely:-

1. **Short title and commencement.** (1) These rules may be called the Rajasthan Value Added Tax (Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. **Amendment of rule 21.** In rule 21 of the Rajasthan Value Added Tax Rules, 2006, hereinafter referred to as the said rules,-

   (i) the existing second proviso to sub-rule (1) shall be substituted by the following, namely:-

   “Provided further that for the assessments pertaining to any period upto 30.06.2017, the dealer may furnish the declaration forms or certificates upto 30.06.2021.”;

   (ii) the existing third proviso to sub-rule (1) shall be deleted; and

   (iii) after the existing proviso to sub-rule (8), the following new proviso shall be added, namely:-
“Provided further that the dealer may submit such application pertaining to any period upto 30.06.2017 by 30.06.2021, directly to the assessing authority concerned and the assessing authority shall dispose such application in accordance with the provisions of this sub-rule, at his own level.”.

3. Amendment of rule 40.- In rule 40 of the said rules,-

(i) in sub-rule (1), for the existing expression “within thirty days from the day on which the gross amount of works contract(s) exceeds rupees ten lacs or upto 31.12.2020, whichever is later.”, the expression “within thirty days from the day on which the gross amount of works contract(s) exceeds rupees ten lacs or upto 30.06.2021, whichever is later:” shall be substituted;

(ii) in sub-rule (1), so amended, the following new proviso shall be added, namely:-

“Provided that where the awardee is a Government Department, or a corporation, company, public undertaking, cooperative society, local body, statutory body or autonomous body in which Government has a share capital, it is not mandatory for such awardee to obtain the Awarder Identification Certificate pertaining to any period upto 30.06.2017.”;

(iii) in sub-rule (8A), for the existing expression “within thirty days of the end of the quarter or upto 31.12.2020, whichever is later.”, the expression “within thirty days of the end of the quarter or upto 30.06.2021, whichever is later.” shall be substituted;

(iv) in sub-rule (8B), for the existing expression “within three months from the close of relevant year or upto 31.12.2020, whichever is later.”, the expression “within three months from the close of relevant year or upto 30.06.2021, whichever is later.” shall be substituted;

(v) in sub-rule (11), for the existing punctuation mark “.” appearing at the end, the punctuation mark “:” shall be substituted; and

(vi) in sub-rule (11), so amended, the following new provisos shall be added, namely:-

“Provided that where the awardee is a Government Department, or a corporation, company, public undertaking, cooperative society, local body, statutory body or autonomous body in which Government has a share capital and has not obtained Awarder Identification Certificate, he shall issue duly filled Form VAT-41 manually to the contractor and the contractor shall submit the same to the Assessing Authority concerned:

Provided further that where such awardee has already issued Form VAT-41 manually to the contractor and the contractor has submitted the same to the Assessing Authority concerned on or before 23rd February, 2021, in such cases, fresh Form VAT-41 shall not be required to be submitted.”.

4. Substitution of Form VAT-41.- The existing Form VAT-41 appended to the said rules shall be substituted by the following, namely:-

“Form VAT-41
[See rule 40(11)]
Certificate of Deduction at Source by Awarder

<table>
<thead>
<tr>
<th>Form No.</th>
<th>Date of Issue</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Name of Contractor
Registration No. (TIN), if any
Address
Name of the Awarder
Awarder Identification No., if any
Address
Amount paid to the contractor
Amount of TDS

<table>
<thead>
<tr>
<th>Details of Tax deducted at source by Awarder</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>S. No.</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>EC No. of Contractor, if any</th>
<th>Amount deducted at source</th>
<th>Voucher No. and date of credit of payment to the contractor</th>
<th>Gross amount of challan &amp; date on which tax deducted at source was deposited to account of the Commercial Taxes Department</th>
<th>Treasury Voucher Number for payments made through AG adjustment/GRN/CIN</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>8</td>
<td>9</td>
<td>10</td>
<td>11</td>
<td>12</td>
</tr>
</tbody>
</table>

It is certified that the above details are complete, true and correct to best of my knowledge and nothing has been concealed.

Date:
Place:

Signature and seal of the person responsible for deduction and deposit of the tax

Name of the Department/Office”.

[No.F.12(29)FD/Tax/2021-270]
By order of the Governor,

(Tina Dabi)
Joint Secretary to Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 24, 2021

S.O.453.-In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 4 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in Schedule VI appended to the said Act, with immediate effect, namely:-
AMENDMENT

In Schedule VI appended to the said Act, the existing serial number 7 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

```
7. Petroleum Crude 5
```

[No.F.12(29)FD/Tax/2021-271]

By order of the Governor,

(Tina Dabi)
Joint Secretary to Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 24, 2021

S.O.454.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) and in supersession of this department's notification numbers F.2(55)FD/Tax/2012-33 dated 12.07.2012, F.4(3)FD/Tax/2018-188 dated 12.02.2018, F.4(3)FD/Tax/2017-113 dated 08.03.2017, F.2(37)FD/Tax/2010-125 dated 08.03.2011, F.4(4)FD/Tax/2020-126 dated 20.02.2020 and F.4(4)FD/Tax/2020-127 dated 20.02.2020, as amended from time to time, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the instruments specified in column number 2 of the table given below shall be reduced and charged at the rate as specified against each of them in column number 3 of the said table:-

<table>
<thead>
<tr>
<th>S.No.</th>
<th>Description of instrument</th>
<th>Stamp duty</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>The lease deed of residential site allotted under the Indira Awaas Yojana and Mukhyamantri Gramin B.P.L. Awaas Yojana</td>
<td>Nil</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>The lease deed or allotment order issued by the Gram Panchayat under rule 157 or 158 of the Rajasthan Panchayati Raj Rules, 1996</td>
<td>Rs. 100</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>The lease deed or allotment order issued under the Rajasthan Government Grants Act, 1961 (Act No. 20 of 1961)</td>
<td>Rs. 100</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>The lease deed or allotment order issued under the Rajasthan Slum Development Policy-2012</td>
<td>Rs. 100</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>The lease deed/sale deed issued/executed under the Chief Minister's Jan Awas Yojana-2015 or</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6. The lease deed issued/executed under the Rajasthan Township Policy-2010,-</td>
<td>0.5% of consideration amount</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------</td>
<td>--------------------------------------------------------------------------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(i) in case of first allotment of plot for residential, institutional, industrial, tourism unit, etc.</td>
<td>at the rate of conveyance on 4 times of the residential conversion charges.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(ii) in case of first allotment of plot for commercial purpose</td>
<td>at the rate of conveyance on 8 times of the residential conversion charges.</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| 7. The lease deed issued/executed in respect of the land placed at the disposal of the Local Authorities under section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 | 120% of the stamp duty payable on the original lease deed |

| 8. The lease deed (not covered under any category specified at serial number 1 to 7 above) issued/executed by the State Government, local authorities, public enterprises or any other Government bodies in respect of land allotted or sold by them. | 120% of the stamp duty payable on the original lease deed |

| 9. Any lease deed covered by serial numbers 2 to 8, submitted for registration after revalidation. | 120% of the stamp duty payable on the original lease deed |

**Note:-**
1. In case of lease deed/sale deed issued/executed under rule 157 or 158 of the Rajasthan Panchayati Raj Rules, 1996 or the Rajasthan Government Grants Act, 1961 or the Rajasthan Slum Development Policy-2012 or the Chief Minister's Jan Awas Yojna-2015 or Pradhan Mantri Awas Yojana or the Rajasthan Township Policy 2010, the allottee shall prove to the satisfaction of the Registration Officer that the lease deed/sale deed has been issued/executed under such Act, Rules, Yojana or Policy, as the case may be.

2. This notification shall be applicable on instruments executed or pending for registration or reference before the Sub-Registrar or for adjudication of stamp duty before Collector (Stamps) or any other Court but stamp duty already paid shall not be refunded.

[No. F.4(2)FD/Tax/2021-272]

By order of the Governor,

(Tina Dabi)

Joint Secretary to the Government
**FINANCE DEPARTMENT**  
**(TAX DIVISION)**  
**NOTIFICATION**  
Jaipur, February 24, 2021  
S.O.455.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) and in supersession of this department's notification number F.4(15)FD/Tax/2014-53 dated 14.07.2014, as amended from time to time, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the following instruments shall be reduced and charged as under:-

<table>
<thead>
<tr>
<th>S. No.</th>
<th>Description of the Instrument</th>
<th>Stamp Duty Payable at the rate of Conveyance</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Every intermediary unregistered and understamped instrument executed on the basis of allotment order in respect of land allotted or sold by the State Government, local authorities, public enterprises or any other Government bodies before getting lease deed from the aforesaid authorities.</td>
<td>On the 1.5 times of the amount of original allotment instead of market value of the property subject to condition that the authority concerned mentioned in column 2 shall issue a certificate stating therein the number of intermediary unregistered and understamped instruments executed in respect of the immovable property and the leaseholder along with his lease deed shall submit such certificate and copies of unregistered and understamped instruments, before the Registering Officer.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| 2     | Every intermediary unregistered and understamped instrument executed in respect of land allotted or sold by housing co-operative societies, before getting the lease deed from the Urban Local Bodies. | (i) On 10% of the market value of the property on the date of presentation before the Sub-Registrar or on the date of reference to the Collector (Stamps), as the case may be, where the document executed upto March 31, 1995;  
(ii) On 20% of the market value of the property on the date of presentation before the Sub-Registrar or on the date of reference to the Collector (Stamps), as the case may be, where the document executed between April 1, 1995 to March 31, 2005;  
(iii) On 30% of the market value of the property on the date of presentation before the Sub-Registrar or on the date of reference to the Collector (Stamps), as the case may be, where the document executed between April 1, 2005 to March 31, 2010;  
(iv) On 35% of the market value of the property on the date of presentation before the Sub-Registrar or on the date of reference to the Collector (Stamps), as the case may be, where...
the document executed between April 1, 2010 to July 14, 2014;

(v) On 40% of the market value of the property on the date of presentation before the Sub-Registrar or on the date of reference to the Collector (Stamps), as the case may be, where the document executed on or after July 15, 2014.

Note: 1. While issuing lease deed, the Urban Local Body concerned shall issue a certificate mentioning the number of intermediary unregistered and understamped instruments executed in respect of the immovable property along with date of their execution and shall also provide the copies of such intermediary instruments;

2. The lease holder along with his lease deed shall submit such certificate and copies of unregistered and understamped instruments, before the Registering Officer.

[No.F.4(2)FD/Tax/2021-273]
By order of the Governor,

(Tina Dabi)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 24, 2021

S.O.456.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) and in supersession of this department's notification number F.12(11)FD/Tax/2013-116 dated 06.03.2013, as amended from time to time, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the gift deeds of immovable property, executed in favour of,-

(i) father, mother, son, brother, sister or husband shall be reduced and charged at the rate of 2.5 percent of the market value of the property;
(ii) daughter or daughter-in-law shall be reduced and charged at the rate of one percent of the market value of the property or rupees one lakh, whichever is less;
(iii) wife,-
(a) shall be exempted if such gift deeds are executed upto March 31, 2022;
(b) shall be reduced and charged at the rate of one percent of the market value of the property or rupees one lakh, whichever is less if such gift deeds are executed after March 31, 2022;

(iv) son's son, son's daughter, daughter's son or daughter's daughter shall be exempted; and

(v) a widow by,-

(a) her deceased husband's mother, father, brother or sister; or

(b) her own mother, father, brother, sister, son or daughter; shall be exempted.

[No.4(2)FD/Tax/2021-274]
By order of the Governor,

(Tina Dabi)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 24, 2021

S.O.457.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) and in supersession of this department's notification number F.4(6)FD/Tax/2016-269 dated 30.03.2016, as amended from time to time, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the release deed of ancestral property specified in clause (a) of Article 48 of the Schedule to the said Act, shall be reduced and charged as under:-

<table>
<thead>
<tr>
<th>S.No.</th>
<th>Description</th>
<th>Rate of Stamp Duty</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Where the market value of the share, interest, part or claim renounced does not exceed rupees 10 lacs.</td>
<td>Five hundred rupees</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Where the market value of the share, interest, part or claim renounced exceeds rupees 10 lacs.</td>
<td>Five thousand rupees</td>
</tr>
</tbody>
</table>

This notification shall also be applicable on instruments executed or instruments pending for registration or reference before the Sub-Registrar or for adjudication of stamp duty before the Collector (Stamps) or any other Court but stamp duty already paid shall not be refunded.

[No.4(2)FD/Tax/2021-275]
By order of the Governor,

(Tina Dabi)
Joint Secretary to the Government
S.O.458.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) and in supersession of this department's notification number F.4(3)FD/Tax/2017-109 dated 08.03.2017, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the instrument relating to conversion of partnership firm, private limited company or unlisted public limited company into limited liability partnership or vice versa shall be reduced and charged at the rate of 0.5 percent.

[No.4(2)FD/Tax/2021-276]
By order of the Governor,

(Tina Dabi)
Joint Secretary to the Government

S.O.459.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the conveyance deed relating to a flat or residential unit, market value of which does not exceed rupees fifty lakh, in a multistorey building exceeding four floors shall be reduced and charged at the rate of four percent, if such conveyance deed is executed and presented for registration upto 30.06.2021.

[No.4(2)FD/Tax/2021-277]
By order of the Governor,

(Tina Dabi)
Joint Secretary to the Government

S.O.460.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) and in partial modification of this department's
notification number F.1(11)FD/Tax Div./97 dated 21.03.1998, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the instrument specified in Article 50 of the Schedule to the said Act shall be reduced and charged at the rate of 0.1 percent subject to maximum of rupees twenty five lakh.

[No.4(2)FD/Tax/2021-278]
By order of the Governor,

(Tina Dabi)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 24, 2021

S.O.461.-In exercise of the powers conferred by section 86 and 87 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), and section 74 of the Indian Stamp Act, 1899 (Central Act No. 2 of 1899), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Stamp Rules, 2004, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Stamp (Amendment) Rules, 2021.
(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Insertion of new rule 29-B.- After the existing rule 29-A and before the existing rule 30 of the Rajasthan Stamp Rules, 2004, the following new rule shall be inserted, namely:-

"29-B. Discount and Remuneration on e-stamps certificate.- (1) The Central Record Keeping Agency authorised by the State Government for the Computerisation of Stamp Duty Administration System in the State hereinafter referred to as the Agency shall be allowed to deduct an amount,-
(i) not exceeding 0.65 percent of the amount collected through sale of e-stamps as may be determined by the State Government, from time to time; and
(ii) equal to that allowed to stamp vendors under rule 29 and 29-A, in respect of e-stamps sold through Authorised Collection Centres.

(2) The Agency shall deduct the amount allowed under sub-rule (1) from the amount collected by it through sale of e-stamps and pay the amount allowed under clause (ii) of sub-rule (1) to the Authorised Collection Centers appointed by it in proportion to the amount collected by them through sale of e-stamps.

(3) The Agency shall produce to the Inspector General of Stamps a quarterly statement of the amount deducted and paid under sub-rule (2)."

[No.4(2)FD/Tax/2021-279]
By order of the Governor,

(Tina Dabi)
Joint Secretary to the Government
S.O.462.-In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-rule (1) and sub-rule (4) of rule 58 of the Rajasthan Stamp Rules, 2004 and in supersession of this department's notification number F.4(4)FD/Tax/2015-226 dated 09.03.2015, as amended from time to time, the State Government hereby determines the rates for assessment of market value of the following categories of land for whole of the State as under:-

1. Rates of land for industrial purposes
Rates of industrial land in RIICO industrial area or land converted for industrial purposes or agriculture land being used for industrial purposes shall be,-
   (i) equal to the rates determined by RIICO in RIICO Industrial Area; and
   (ii) equal to three times of the rates of agriculture land of that area in other cases but if such rates are more than the rates determined by RIICO in nearest RIICO Industrial Area then equal to the rates determined by RIICO in that nearest RIICO Industrial Area.

2. Rates of land for institutional, residential and commercial purposes in RIICO Industrial Area
Rates of institutional, residential and commercial land in RIICO Industrial Area shall be,-
   (i) equal to the rates of industrial land determined by RIICO in case of institutional land;
   (ii) equal to two times of the rates of industrial land determined by RIICO in case of residential land; and
   (iii) equal to four times of the rates of industrial land determined by RIICO in case of commercial land.

3. Rates of land for institutional purposes outside RIICO Industrial Area
Rates of land converted for institutional purposes or agriculture land is being used for institutional purposes shall be,-
   (i) equal to 1.5 times of the rate of agriculture land of that area where land is purchased by cooperative societies/charitable institutions; and
   (ii) equal to 2 times of the rate of agriculture land of that area in other cases.

**Explanation:** (i) In areas where rates of agriculture land are not recommended by the District Level Committee, rates of institutional land shall be equal to the rates of residential land of that area.
   (ii) Institution shall include educational institutions, training institutions, coaching institutions, hostels, hospitals, banks, financial institutions, insurance companies etc.

4. Rates of land for Solar Power Plant, Solar Park, Wind Power Plant or Hybrid Power Plant purposes
Rates of land converted for Solar Power Plant, Solar Park, Wind Power Plant or Hybrid Power Plant purposes or agriculture land is being used for Solar Power Plant, Solar Park, Wind Power Plant or Hybrid Power Plant purposes shall be equal to two times of the rates of agriculture land of that area but if such rates are more than the rates determined by the RIICO
5. Rates of land for agro-industrial purposes
Rates of land converted for agro-industrial purposes or agriculture land is being used for agro-industrial purposes shall be equal to two times of the rates of agriculture land of that area.

6. Rates of land for mining purposes
   (i) In case of agriculture land purchased for mining purposes or agriculture land in respect of which consent deed is executed between land owner and lessee for mining purposes shall be equal to three times of the rates of agriculture land of that area and where the rates of agriculture land of that area are not determined, the rates of agriculture land of the adjoining area.
   (ii) In case of new mining lease (whether granted through auction or otherwise), renewal of mining lease or transfer of mining lease shall be equal to four times of the rates of agriculture land of that area and where rates of agriculture land of that area are not determined, the rates of agriculture land of the adjoining area.

Explanation: The above rates shall also be applicable on the instruments executed or pending for registration or reference before the Sub-Registrar or for adjudication before the Collector (Stamps) or any other Court but stamp duty already paid shall not be refunded.

7. Rates of land for Resort purposes
Rates of the land converted for resort purposes or agriculture land is being used for resort purposes shall be,-
   (i) equal to the rates of commercial land of that area for portion on which construction has been done or the maximum permissible constructed area, whichever is higher; and
   (ii) equal to 2 times of the rates of agriculture land of that area for remaining part of the land.

8. Rates of land for hotel, motel, guest house and restaurant purposes
Rates of the land converted for hotel, motel, guest house and restaurant purposes or land is being used for the above purposes shall be equal to the rates of the commercial land of that area.

9. Rates of land for marriage garden purposes
Rates of the agriculture land is being used for marriage garden purposes or land converted for marriage garden purposes shall be,-
   (i) equal to the rates of commercial land of that area for portion on which construction has been done or the maximum permissible constructed area, whichever is higher; and
   (ii) equal to 1.5 times of the rates of residential land of that area for remaining part of land.

10. Rates of agriculture land purchased by companies, firms or institutions
Rates of the agriculture land purchased by companies, firms or institutions shall be equal to the rates of agriculture land of that area.
11. Rates of land for farm house purposes
Rates of the agriculture land is being used for farm house purposes or land converted for farm house purposes shall be,-

(i) equal to rates of residential land of that area where the area of the land is upto 1000 sq. meter;

(ii) equal to the rates of residential land of that area for 500 sq. meter or portion on which construction has been done, whichever is higher, and equal to two times the rates of agricultural land of that area for remaining portion, where the total area of the farm house is more than 1000 sq. meter but less than 2500 sq. meter; and

(iii) equal to the rates of residential land of that area for 500 sq. meter or portion on which construction has been done, whichever is higher, and equal to 1.5 times the rates of agricultural land of that area for remaining portion, where the total area of the farm house is 2500 sq. meter or more.

12. Rates of residential or commercial plots having area more than 3000 sq. meter
Rates of residential or commercial plots having area more than 3000 sq. meter, shall be reduced by 5 percent of the existing rates for such categories of lands.

13. Rates of corner plots
Rates of corner plots, except plots of agriculture land having area more than 1000 sq. meter, shall be 10% more.

14. Rates of land for which mixed land use patta/lease deed has been issued
On sale or transfer of vacant land, for which patta/lease deed of mixed land use has been issued by Development Authorities or Urban Improvement Trusts or other Local Bodies, the rate of such land shall be equal to 50% of the rate of commercial land of that area.

15. Rates of land under different land use
Rates of land which is being used for the purpose other than its approved use shall be equal to the rates of the category of its actual use or its approved use, whichever is higher.

16. Rates of residential and commercial land of a particular area where rates of such land are not recommended by the District Level Committee

(i) Rates of residential land shall be three times of the rates of agriculture land of that area; and

(ii) Rates of commercial land shall be six times of the rates of agriculture land of that area.

17. Rates of agriculture land having area upto 1000 sq. meter situated within the limits of periphery belt of urban areas
Rates of agriculture land having area upto 1000 sq. meter situated in urban areas or urbanisable limits or in periphery belt of urban areas as defined in section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956), shall be equal to the rates of residential land of that area.

Explanation: (i) The above rates shall be applicable on the instrument of sale.

(ii) Where in the instrument of sale of agriculture land the numbers of buyers are more than one and share of any buyer is 1000 square meter or less,
value of such share of land shall be calculated at the rate of residential land of that area.

18. Rates of agriculture land having area upto 500 sq. meter situated outside the limits of periphery belt of urban areas

Rates of agriculture land having area upto 500 sq. meter situated outside the periphery belt of urban areas as defined in section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956), except where such land comprises in a single khasra or where such land is purchased by a khatedar of the adjoining agriculture land, shall be equal to the rates of residential land of that area.

Explanation: (i) The above rates shall be applicable on the instrument of sale.

(ii) Where in the instrument of sale of agriculture land the number of buyers are more than one and share of any buyer is 500 square meters or less, value of such share of land shall be calculated at the rate of residential land of that area.

(iii) The above rates shall also be applicable on instruments executed or pending for registration or reference before the Sub-Registrar or for adjudication of stamp duty before the Collector (Stamps) or any other Court but stamp duty already paid shall not be refunded.

[No.4(2)FD/Tax/2021-280]
By order of the Governor,

(Tina Dabi)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT (TAX DIVISION)
NOTIFICATION
Jaipur, February 24, 2021

S.O.463.-In exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 58 of the Rajasthan Stamp Rules, 2004, the State Government being of the opinion that the circumstances require so to do, hereby orders that the existing rates of residential and commercial categories of land shall be re-determined and decreased by ten percent with effect from 24.02.2021.

[No.4(2)FD/Tax/2021-281]
By order of the Governor,

(Tina Dabi)
Joint Secretary to the Government
FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 24, 2021

S.O.464.-In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-rule (1) of rule 58 of the Rajasthan Stamp Rules, 2004 and in supersession of this department's notification number F.4(4)FD/Tax/2015-225 dated 09.03.2015, as amended from time to time, the State Government hereby specifies the criteria on the basis of which market value of the proportionate land under the multistoried building shall be assessed:-

<table>
<thead>
<tr>
<th>S.No.</th>
<th>Description of unit</th>
<th>Method of valuation of the land</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>On transfer of a unit on ground floor without the rights of roof</td>
<td>70% of the assessed market value of the land</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>On transfer of a unit on first or second floor without the rights of roof</td>
<td>60% of the assessed market value of the land</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>On transfer of a unit on basement without the rights of roof</td>
<td>50% of the assessed market value of the land</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>On transfer of a unit on third or above floor without the rights of roof</td>
<td>40% of the assessed market value of the land</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>On transfer of a unit with the rights of roof</td>
<td>100% of the assessed market value of the land</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Explanation: (i) The rate of valuation of proportionate land shall be determined in accordance with the use of the unit specified in the approved layout plan or actual use of the unit, whichever is higher.
(ii) This notification shall also be applicable on instruments executed or instruments pending for registration or reference before the Sub-Registrar or for adjudication of stamp duty before the Collector (Stamps) or any other Court but stamp duty already paid shall not be refunded.

[No.4(2)FD/Tax/2021-282]
By order of the Governor,

(Tina Dabi)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 24, 2021

S.O.465.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Registration Act, 1908 (Central Act No. 16 of 1908), the State Government hereby makes the
following amendments in this department's notification number F.2(17)FD/Tax/2010/part-225 dated 02.09.2020, namely:-

**AMENDMENTS**

In table of the said notification,-

A. in column number 4 and 5, against serial number 5, after the existing expression

<table>
<thead>
<tr>
<th>(xvii) Kalyanpur</th>
<th>Sub Tehsil Kalyanpur</th>
</tr>
</thead>
</table>

the expression

<table>
<thead>
<tr>
<th>(xviii) Dhanau</th>
<th>Tehsil Dhanau</th>
</tr>
</thead>
</table>

shall be added;

B. in column number 5,-

(i) against serial number 8, for the existing expression "Sub Tehsil Bajju", the expression "Tehsil Bajju" shall be substituted; and

(ii) against serial number 12, for the existing expression "Sub Tehsil Mandawar", the expression "Tehsil Mandawar" shall be substituted;

C. the existing serial number 16 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

<table>
<thead>
<tr>
<th>16</th>
<th>Jaipur Revenue district Jaipur</th>
<th>(i) Jaipur Tehsil Jaipur, Tehsil Amber, Tehsil Bassi, Tehsil Chaksu, Tehsil Chomu, Tehsil Dudu, Tehsil Jamwaramgarh, Tehsil Phagi, Tehsil Sanganer</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(ii) Viratnagar Tehsil Viratnagar</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(iii) Govindgarh Sub Tehsil Govindgarh</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(iv) Khejroli Sub Tehsil Khejroli</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(v) Mojamabad Tehsil Mojamabad</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(vi) Kishangarh Renwal Tehsil Kishangarh Renwal</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(vii) Kotkhawada Tehsil Kotkhawada</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(viii) Kotputli Tehsil Kotputli</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(ix) Sambher Tehsil Sambher</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(x) Shahpura Tehsil Shahpura</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(xi) Madhorajpura Sub Tehsil Madhorajpura</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(xii) Andhi Sub Tehsil Andhi</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(xiii) Tunga Sub Tehsil Tunga</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(xiv) Amarsar Sub Tehsil Amarsar</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(xv) Manoharpur Sub Tehsil Manoharpur</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(xvi) Pawta Tehsil Pawta</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(xvii) Kalwar Sub Tehsil Kalwar</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

D. in column number 5, against serial number 19,-

(a) for the existing expression "Sub Tehsil Sunail", the expression "Tehsil Sunail" shall be substituted; and
S.O.466.-In exercise of the powers conferred by section 6 of the Registration Act, 1908 (Central Act No. 16 of 1908), the State Government hereby makes the following amendments in this department's notification number F.2(17)FD/Tax/2010/part-226 dated 02.09.2020, namely:-

AMENDMENTS

In table of the said notification,-

A. in column number 3 and 4, against serial number 5, after the existing expression "(xvii) Naib Tehsildar, Kalyanpur Kalyanpur",

the expression "(xviii) Tehsildar, Dhanau Dhanau"

shall be added;

B. in the column number 3,-

(i) against serial number 8, for the existing expression "(iv) Naib Tehsildar, Bajju", the expression "(iv) Tehsildar, Bajju" shall be substituted; and

(ii) against serial number 12, for the existing expression "(x) Naib Tehsildar, Mandawar", the expression "(x) Tehsildar, Mandawar" shall be substituted;

C. the existing serial number 16 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Jaipur</th>
<th>Sub-Registrar, Jaipur-I</th>
<th>Sub-Registrar, Jaipur-II</th>
<th>Sub-Registrar, Jaipur-III</th>
<th>Sub-Registrar, Jaipur-IV</th>
<th>Sub-Registrar, Jaipur-V</th>
<th>Sub-Registrar, Jaipur-VI</th>
<th>Sub-Registrar, Jaipur-VII</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>16</td>
<td>Jaipur</td>
<td>(i)</td>
<td>(ii)</td>
<td>(iii)</td>
<td>(iv)</td>
<td>(v)</td>
<td>(vi)</td>
<td>(vii)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

By order of the Governor,

(Tina Dabi)
Joint Secretary to the Government
| (viii) Sub-Registrar, Jaipur-VIII | (xv) Sub-Registrar, Chaksu |
| (ix) Sub-Registrar, Jaipur-IX | (xvi) Sub-Registrar, Chomu |
| (x) Sub-Registrar, Jaipur-X | (xvii) Sub-Registrar, Dudu |
| (xi) Sub-Registrar, Sanganer-I | (xviii) Sub-Registrar, Jamwaramgarh |
| (xii) Sub-Registrar, Sanganer-II | (xix) Sub-Registrar, Phagi |
| (xiii) Sub-Registrar, Amber | (xx) Naib Tehsildar, Bagru |
| (xiv) Sub-Registrar, Bassi | (xxi) Naib Tehsildar, Mundota |
| | (xxii) Naib Tehsildar, Jalsu |
| | (xxiii) Naib Tehsildar, Rampura Dabri |
| | (xxiv) Naib Tehsildar, Govindgarh |
| | (xxv) Naib Tehsildar, Khejroli |
| | (xxvi) Tehsildar, Viratnagar |
| | (xxvii) Tehsildar, Mojamabad |
| | (xxviii) Tehsildar, Kishangarh Renwal |
| | (xxix) Tehsildar, Kotkhawada |
| | (xxx) Sub-Registrar, Kotputli |
| | (xxxi) Sub-Registrar, Sambhar |
| | (xxxii) Sub-Registrar, Shahpura |
| | (xxxiii) Sub-Registrar, Madhorajpura |
| | (xxxiv) Naib Tehsildar, Andhi |
| | (xxxv) Naib Tehsildar, Tunga |
| | (xxxvi) Naib Tehsildar, Amarsar |
| | (xxxvii) Naib Tehsildar, Manoharpura |
| | (xxxviii) Tehsildar, Pawta |
| | (xxxix) Naib Tehsildar, Kalwar |

Area of Tehsil Bassi of Sub District Jaipur
Area of Tehsil Chaksu of Sub District Jaipur
Area of Tehsil Chomu of Sub District Jaipur
Area of Tehsil Dudu of Sub District Jaipur
Area of Tehsil Jamwaramgarh of Sub District Jaipur
Area of Tehsil Phagi of Sub District Jaipur
Area of Sub Tehsil Bagru of Sub District Jaipur
Area of Sub Tehsil Mundota of Sub District Jaipur
Area of Sub Tehsil Jalsu of Sub District Jaipur
Area of Sub Tehsil Rampura Dabri of Sub District Jaipur
Area of Sub Tehsil Govindgarh of Sub District Jaipur
Area of Sub Tehsil Khejroli of Sub District Jaipur
Viratnagar
Mojamabad
Kishangarh Renwal
Kotkhawada
Kotputli
Sambhar
Shahpura
Madhorajpura
Andhi
Tunga
Amarsar
Manoharpura
Pawta
Kalwar
D. in column number 3, against serial number 19,-
   (a) for the existing expression "(vii) Naib Tehsildar, Sunail", the expression
   "(vii) Tehsildar, Sunail" shall be substituted; and
   (b) for the existing expression "(x) Naib Tehsildar, Bakani", the expression
   "(x) Tehsildar, Bakani" shall be substituted; and
E. in column number 3, against serial number 29, for the existing expression "(xix) Naib
   Tehsildar, Rawla", the expression "(xix) Tehsildar, Rawla" shall be substituted.

[No.4(2)FD/Tax/2021-284]
By order of the Governor,

(Tina Dabi)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 24, 2021

S.O.467.-In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 69 of the
Registration Act, 1908 (Central Act No. 16 of 1908), the State Government hereby approve
and publish the following rules further to amend the Rajasthan Registration Rules, 1955,
made by the Inspector General of Registration, Rajasthan in exercise of the powers conferred
on him by sub-section (1) of the section 69 of the said Act, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan
Registration (Amendment ) Rules, 2021.
   (2) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of rule 79.- The existing rule 79 of the volume-I of the Rajasthan
Registration Rules, 1955 shall be substituted by the following, namely:-

   “79. Refund of fees.- (1) In the event of registration being refused, or not taking place
   for other reasons, any fees which may have been levied will be refunded except fees for
   commissions, summons, attendances, and travelling allowances, where such fees have been
   earned.

   (2) Inspection or search fees may be refunded in cases where no inspection or search
   is made, but shall not be refunded where a partial inspection or search has been made.

   (3) Any registration fees charged by a registering officer in excess of what is actually
   chargeable under the rule may be refunded at the discretion of the Collector (Stamps)
   provided that the refund is claimed within six months and the Collector (Stamps) is satisfied
   that there has been a clear over-charge.

   (4) Application for refund of fees will be in writing to the Collector (Stamps) who
   will pass orders thereon. The Collector (Stamps) will be responsible for seeing that receipts
   are obtained and recorded for the full amount of fees to be refunded.”.
[No.4(2)FD/Tax/2021-285]
By order of the Governor,

(Tina Dabi)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 24, 2021

S.O.468. In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 78 of the Registration Act, 1908 (Central Act No. 16 of 1908) and in supersession of this department's notification number F.4(3)FD/Tax/2017-123 dated 08.03.2017, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that the registration fees chargeable in excess of rupees ten thousand on the instrument relating to conversion of partnership firm, private limited company or unlisted public limited company into limited liability partnership or vice versa shall be remitted.

[No.4(2)FD/Tax/2021-286]
By order of the Governor,

(Tina Dabi)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 24, 2021

S.O.469. In exercise of the powers conferred by section 22 of the Chapter IV of the Rajasthan Finance Act, 2020 (Act No. 9 of 2020), the State Government considers it expedient in the public interest so to do, hereby orders that interest and penalty payable on land tax shall be remitted where arrears of land tax is deposited upto 30.06.2021.

[No.4(2)FD/Tax/2021-287]
By order of the Governor,

(Tina Dabi)
Joint Secretary to the Government

TRANSPORT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Jaipur, February 24, 2021

S.O.470.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government, being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby exempts the new stage carriage passenger vehicles, purchased on or after 01.04.2021 and registered upto 31.03.2022 and plying exclusively on rural routes and other routes (as classified under the provisions of the Rajasthan Motor Vehicles Rules, 1990) from the payment of motor vehicle tax payable under section 4 of the said Act for a period of three years from the date of their registration.

[No.F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/2021-22/1]

By Order of the Governor,

(Mahendra Kumar Khinchi)
Joint Secretary to the Government

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION
Jaipur, February 24, 2021

S.O.471.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No.11 of 1951), the State Government hereby,-

(i) exempts from payment of Motor Vehicle Tax, Special Road Tax, Surcharge, penalty and interest, if any, payable on destroyed vehicles if Motor Vehicle Tax, Special Road Tax and Surcharge payable upto the date on which vehicle was destroyed is deposited on or before 31.03.2021;

(ii) exempts from payment of penalty and interest payable on Motor Vehicle Tax, Special Road Tax, One Time Tax, Lump Sum Tax and Surcharge upto 31.01.2021 on vehicle other than the destroyed vehicles, if,-

(a) penalty and interest, if any, due after 31.01.2021 on Motor Vehicle Tax, One Time Tax and Surcharge is deposited on or before 31.03.2021; and

(b) any due Motor Vehicle Tax, Special Road Tax, One Time Tax, Lump Sum Tax and Surcharge is deposited on or before 31.03.2021; and

(iii) exempts from payment of penalty and interest payable on One Time Tax and Surcharge upto 31.01.2021 on non-transport vehicles registered outside the State and brought into the State for use exceeding thirty days, if One Time Tax and Surcharge due upto 31.01.2021 is deposited on or before 31.03.2021.

Above exemption shall be subject to following conditions, namely:-

(i) The vehicle owner may apply before the Taxation Officer for the exemption.

(ii) The Taxation Officer shall calculate the tax and shall issue demand notice.

(iii) The Registration Certificate of destroyed vehicles shall be cancelled by the Registering Authority.
(iv) The amount of Motor Vehicle Tax, Special Road Tax including surcharge, penalty or interest, if any, paid earlier shall not be refunded.
(v) If any dispute arises regarding exemption, the decision of the Transport Commissioner shall be final.

Explanation: The date of destruction of the vehicle shall be determined in accordance with the procedure specified by the Transport Commissioner.

[No.F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/2021-22/2]
By Order of the Governor,

(Mahendra Kumar Khinchi)
Joint Secretary to the Government

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION
Jaipur, February 24, 2021

S.O.472.-In exercise of the powers conferred by clause (a) and clause (c) of sub-section (1) of section 4 read with section 3 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government hereby makes the following amendments in this department's notification number F.6(179)Pari/Tax/Hqrs/2019-20/3 dated 10.07.2019, as amended from time to time, with effect from 01.04.2021, namely:-

AMENDMENTS

In the said notification,-

(i) against serial number 2 of the table, the existing item (b) of column 2 and entries relating thereto of column 2 and column 3 shall be substituted by the following, namely:-

<table>
<thead>
<tr>
<th>(b) Other routes</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(i) plying upto 100 km. per day</td>
<td>Rs. 230/- per seat per month</td>
</tr>
<tr>
<td>(ii) plying above 100 km. and upto 150 km. per day</td>
<td>Rs. 250/- per seat per month</td>
</tr>
<tr>
<td>(iii) plying above 150 km. and upto 200 km. per day</td>
<td>Rs. 280/- per seat per month</td>
</tr>
<tr>
<td>(iv) plying above 200 km. and upto 250 km. per day</td>
<td>Rs. 300/- per seat per month</td>
</tr>
<tr>
<td>(v) plying above 250 km. and upto 300 km. per day</td>
<td>Rs. 320/- per seat per month</td>
</tr>
<tr>
<td>(vi) plying above 300 km. and upto 350 km. per day</td>
<td>Rs. 520/- per seat per month</td>
</tr>
<tr>
<td>(vii) plying above 350 km. and upto 400 km. per day</td>
<td>Rs. 540/- per seat per month</td>
</tr>
<tr>
<td>(viii) plying above 400 km. per day</td>
<td>Rs. 560/- per seat per month</td>
</tr>
</tbody>
</table>
(ii) against serial number 7 of the table, the existing item (a) of column 2 and entries relating thereto of column 2 and column 3 shall be substituted by the following, namely:-

<table>
<thead>
<tr>
<th>(a)</th>
<th>More than three wheeled motor vehicles plying on non-temporary permits</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(i)</td>
<td>with seating capacity more than 22 and upto 32</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Rs. 700/- per seat per month</td>
</tr>
<tr>
<td>(ii)</td>
<td>with seating capacity more than 32</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Rs. 700/- per seat per month subject to a maximum of Rs. 40,000/- per month</td>
</tr>
<tr>
<td>(iii)</td>
<td>sleeper bus</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Rs. 510/- per seat per month subject to a maximum of Rs. 40,000/- per month</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(iii) in proviso,-

(a) after the existing clause (iii) and before the existing clause (iv), the following new clause (iii-a) shall be inserted, namely :-

"(iii-a) in case of the motor vehicle falling under sub-clauses (i) and (ii) of clause (a) in column 2 against serial number 7 and plying exclusively within the revenue divisional limits, the tax shall be 50% of the tax payable on such motor vehicle;"; and

(b) after the existing clause (viii) and before the existing note, the following new clause (ix) shall be inserted, namely :-

"(ix) passenger vehicles registered for the first time on or after 01.03.2021 shall be exempted from tax payable as specified in column 3 against serial number 13, if the vehicle is covered by a non-temporary permit within 15 days from the date of registration."

[No.F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/2021-22/3D]
By Order of the Governor,

(Mahendra Kumar Khinchi)
Joint Secretary to the Government

TRANSPORT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Jaipur, February 24, 2021

S.O.473.-In exercise of the powers conferred by clause (a), clause (c) and clause (cc) of sub-section (1) of section 4 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government hereby makes the following amendment in this department's notification number F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/2019-20/4 dated 10.07.2019, with effect from 01.04.2021, namely :-

Amendment
In table of the said notification, against serial number 1, the existing item (b) of column 2 and entries relating thereto of column 2 and 3 shall be substituted by the following, namely:

| (b) any other transport vehicle not covered under any category above or vehicle such as Dumper, Loader, Camper Vans, Trailers, Tipper, Cash Van, Mobile Canteen, Haul Pack Dumper, Mobile Work Shops, Ambulance, Animal Ambulance, Fire Tenders, Snorked Ladders, Auxiliary Trailers and Fire Fighting Vehicles, Hearse, Mail Carrier, Mobile Clinic, X-Ray Vans, Library Vans etc. having G.V.W. more than 16500 Kg. | Rs. 1800 per 1000 Kg. of G.V.W. or part thereof per year subject to a maximum of Rs. 35000/- |

[No.F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/2021-22/4A]

By Order of the Governor,

(Mahendra Kumar Khinchi)
Joint Secretary to the Government

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, February 24, 2021

S.O.474.-In exercise of the powers conferred by section 22 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Rules, 1951, namely:-

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Rajasthan Motor Vehicles Taxation (Amendments) Rules, 2021.

   (2) They shall come into force with immediate effect.

2. **Amendment of rule 25.**- The existing sub-rule (2) of rule 25 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Rules, 1951, hereinafter referred to as the said rules, shall be substituted by the following, namely: -

   "(2) The period of surrender or non-use shall not be less than seven days for stage carriages and less than thirty days for other than stage carriages. The period of such surrender shall not be more than ninety days for all categories of vehicles except in case of theft of the vehicle."

3. **Amendment of rule 41.**- In rule 41 of the said rules, for the existing expression "the driver shall be excluded", the expression "the driver and conductor shall be excluded" shall be substituted.
S.O.475.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government hereby, with immediate effect, exempts from payment of fifty percent of the additional One Time Tax payable at the time of transfer of ownership of two wheeled non-transport vehicles and four wheeled non-transport vehicles having seating capacity upto ten.

This notification shall remain in force upto 31.03.2022.

S.O.476.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 200 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988), and in supersession of this department's notification number F.7(47)Pari/Rules/H.Q./87/part/12409 dated 08.07.2020, the State Government hereby authorises following officers to compound the offences committed and punishable under sections of the said Act, mentioned in column number 2 and 3 of the Schedule given below, for the amount specified in column number 4 against each of them of the said Schedule:-

(1) Officers of the Transport Department not below the rank of Motor Vehicle Sub-Inspector, for whole of the State;
(2) Officers of Traffic Police and Police not below the rank of Head Constable, for Jaipur and Jodhpur Commissionerate areas;
(3) Officers of Traffic Police and Police not below the rank of Assistant Sub-Inspector, for remaining part of state in their respective areas except Jaipur and Jodhpur Commissionerate areas; and
(4) Officers attached with Mobile Traffic units not below the rank of Head Constable, for whole of the State:
Provided that the officers of the Police and Traffic Police are not authorised to compound the offences committed and punishable under sub-section (1) of sections 182A, sub-section (3) of section 182A, sub-section (4) of section 182A, section 182B, section 192A, sub-section (1) of section 194 (read with sections 113, 114), sub-section (1A) of section 194 and sub-section (2) of section 194.

**SCHEDULE**

<table>
<thead>
<tr>
<th>S. No.</th>
<th>Sections under which the offence committed is to be compounded</th>
<th>Offences</th>
<th>Amount for which the offence is to be compounded (in Rupees)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>177</td>
<td>General provisions for punishment of offences</td>
<td>For first offence-&lt;ul&gt;&lt;li&gt;(i) 100/- for Two Wheeler/ e-Rickshaw/ Three Wheeler&lt;/li&gt;&lt;li&gt;(ii) 200/- for other than above&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;For subsequent offence-&lt;ul&gt;&lt;li&gt;(i) 200/- for Two Wheeler/ e-Rickshaw/ Three Wheeler&lt;/li&gt;&lt;li&gt;(ii) 400/- for other than above&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>178(1)</td>
<td>Travelling without pass or ticket in a stage carriage</td>
<td>100/-</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>178(2)</td>
<td>Dereliction of duty on the part of Conductor of a stage carriage</td>
<td>500/-</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>178(3)(a)</td>
<td>Refusal to ply or carry the passengers by the driver of a two-wheeled or three-wheeled contract carriage</td>
<td>50/-</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>178(3)(b)</td>
<td>Refusal to ply or carry the passengers by the driver of a contract carriage other than two-wheeled or three-wheeled contract carriage</td>
<td>200/-</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>179(1)</td>
<td>Disobedience of any direction or obstructs any function by a Driver</td>
<td>500/-</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>179(2)</td>
<td>Refusal to give information or gives false information</td>
<td>1000/-</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>180</td>
<td>Allowing Unauthorised person to drive vehicle</td>
<td>5000/-</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>181</td>
<td>Driving without having a valid license</td>
<td>5000/-</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>182(1)</td>
<td>Driving a motor vehicle in a public place after disqualification under the Act or applies for or obtains a</td>
<td>10000/-</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11.</td>
<td>182(2)</td>
<td>Act as a Conductor of a stage carriage in a public place after disqualification or applies for or obtains a conductor license without disclosing the endorsement made on a Conductor’s license which is previously held</td>
<td>1000/-</td>
</tr>
<tr>
<td>12.</td>
<td>182A(1)</td>
<td>Offences relating to sale or delivery or alteration of motor vehicles by dealer, Manufacturer or importer violating chapter VII or rules and regulations made thereunder</td>
<td>1,00,000/- per such vehicle</td>
</tr>
<tr>
<td>13.</td>
<td>182A(3)</td>
<td>Offences relating to sale of critical safety component which does not comply with chapter VII or rules and regulations made thereunder</td>
<td>1,00,000/- per such component</td>
</tr>
<tr>
<td>14.</td>
<td>182A(4)</td>
<td>Alteration of motor vehicle by owner not permitted under the Act or the Rules and regulations made thereunder</td>
<td>5000/- per such alteration</td>
</tr>
<tr>
<td>15.</td>
<td>182 B</td>
<td>Punishment for contravention of section 62 A (Prohibition of registration and issuance of certificate of fitness to over sized vehicle)</td>
<td>5000/-</td>
</tr>
<tr>
<td>16.</td>
<td>183(1)(i)</td>
<td>Drives or causes any person to drive LMV with excess speed</td>
<td>For first offence-1000/- For the second or any subsequent offence under this sub-section the driving license of such driver shall be impounded as per the provisions of section 206(4)</td>
</tr>
<tr>
<td>17.</td>
<td>183 (1)(ii)</td>
<td>Drives or causes any person to drive a Medium or Heavy Goods or Passenger vehicle with excess speed</td>
<td>For first offence- 2000/- For the second or any subsequent offence under this sub-section the driving license of such driver shall be impounded as per the provisions of section 206(4)</td>
</tr>
<tr>
<td>18.</td>
<td>184 (c)</td>
<td>Driving Dangerously (only to the extent to the use of Handheld communication device)</td>
<td>For first offence-1000/- For subsequent offence-10000/-</td>
</tr>
<tr>
<td>19.</td>
<td>186</td>
<td>Driving when mentally or physically unfit to drive</td>
<td>For first offence-500/- For subsequent offence-1000/-</td>
</tr>
<tr>
<td>20.</td>
<td>189</td>
<td>Racing and trials of speed without the written consent of state</td>
<td>For first offence-5000/- For subsequent offence-10000/-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
|   | 190(2) | Drives or causes or allows to be driven, in any public place a motor vehicle, which violates the standards prescribed in relation to road safety, control of noise and air pollution | For first offence-  
(i) 500/- for Two Wheeled/e-rickshaw/Three Wheeled Motor Vehicles  
(ii) 1000/- for Non-transport vehicle other than two wheeled and three wheeled Non- transport vehicle  
(iii) 1500/- for LMV Transport (other than two wheeled/e-rickshaw/three wheeled transport vehicle)  
(iv) 2000/- for Medium/Heavy Transport vehicles  
For Subsequent offence-  
(i) 1000/- for Two Wheeled/e-rickshaw/Three Wheeled Motor Vehicles  
(ii) 2000/- for Non-transport vehicle other than two wheeled and three wheeled Non-transport vehicle  
(iii) 3000/- for LMV Transport (other than two wheeled/e-rickshaw/three wheeled transport vehicle)  
(iv) 4000/- for Medium/Heavy Transport vehicles |
|---|---|---|---|
| 22. | 192 | Using vehicle without registration or fitness:  
(i) Two wheeled or three wheeled motor vehicle  
(ii) Passenger vehicles other than Two wheeled or three wheeled motor vehicle  
(iii) Agriculture Tractor/ trailer  
(iv) Goods vehicle | For first offence-2000/-  
For subsequent offence-5000/-  
For first offence-5000/-  
For subsequent offence-10000/-  
For first offence-2000/-  
For subsequent offence-5000/-  
For first offence-5000/-  
For subsequent offence-10000/- |
| 23. | 192 A | Using vehicle without permit or violation of permit conditions | 10000/- for HMV  
5000/- for LMV/MMV  
2000/- for Two Wheeler/Three Wheeler & Stage Carriage Bus plying exclusively on urban routes |
| 24. | 194(1) | Driving Vehicle,-  
(i) exceeding permissible weight in contravention of section | 5000/- and additional 1000/- per ton of excess load together with the liability to pay charges for |
<p>| | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>113, 114</td>
<td>off-loading of excess load</td>
</tr>
<tr>
<td>ii) in contravention of section 115 (driving in prohibited/ restricted area)</td>
<td></td>
<td>5000/-</td>
</tr>
<tr>
<td>25.</td>
<td>194(1A)</td>
<td>Driving a motor vehicle carrying over dimension projections</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>5000/- together with the liability to pay charges for off-loading of such load</td>
</tr>
<tr>
<td>26.</td>
<td>194(2)</td>
<td>Refuses to stop and submit his vehicle to weighing after being directed by authority</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>10000/-</td>
</tr>
<tr>
<td>27.</td>
<td>194 A</td>
<td>Carrying excess passenger in transport vehicle</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>200/- per excess passenger</td>
</tr>
<tr>
<td>28.</td>
<td>194 B(1)</td>
<td>Driver or passenger without seat belt</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1000/-</td>
</tr>
<tr>
<td>29.</td>
<td>194 B(2)</td>
<td>Carrying children below 14 years without safety belt/child restraint system</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>500/-</td>
</tr>
<tr>
<td>30.</td>
<td>194 C</td>
<td>Riding more than two persons on two wheeler</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>100/-</td>
</tr>
<tr>
<td>31.</td>
<td>194 D</td>
<td>Riding without helmets by driver &amp; rider</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1000/-</td>
</tr>
<tr>
<td>32.</td>
<td>194 E</td>
<td>Not providing way for emergency vehicles (Fire Service or Ambulance)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1000/-</td>
</tr>
<tr>
<td>33.</td>
<td>194F(a)</td>
<td>1. Using horn needlessly or continuously  2. Using horn in prohibited area</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>500/- for Two/Three Wheeler  1000/- for other than above</td>
</tr>
<tr>
<td>34.</td>
<td>194F(b)</td>
<td>Release of exhaust gas other than silencer</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>500/- for Two/Three Wheeler  1000/- for other than above</td>
</tr>
<tr>
<td>35.</td>
<td>196</td>
<td>Driving Uninsured vehicle</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1000/- for Two/Three Wheeler  2000/- for other than above</td>
</tr>
<tr>
<td>36.</td>
<td>198</td>
<td>Unauthorized interference with vehicle</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1000/-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

[No.F.7(47)/Pari/Rule/H.Q./87/part/1/1]
By Order of the Governor,
(Mahendra Kumar Khinchi)
Joint Secretary to the Government

TRANSPORT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Jaipur, February 24, 2021

S.O.477.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 200 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988), the State Government hereby authorises the
District Transport Officer to compound the offences found committed on or before 31.01.2021 under clause (b) of sub-section (3) of section 113 of the said Act, on the basis of information received through e-ravanna of Mines Department, for the compounding amount as specified in column 3 of the table given below, subject to the amount specified in column 4 of the said table.

<table>
<thead>
<tr>
<th>S. No.</th>
<th>Total compounding amount payable for a vehicle upto 31.01.2021 on the basis of this department's notification No.F.7(47)pari/rules/HQ/Part/12409 dated 08.07.2020 (in Rs.)</th>
<th>Compounding amount (percentage of amount payable for a vehicle upto 31.01.2021 on the basis of this department's notification No.F.7(47)pari/rules/HQ/Part/12409 dated 08.07.2020)</th>
<th>Minimum payable Compounding amount (in Rs.)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Upto 1 lakh</td>
<td>25%</td>
<td>5500/-</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Above 1 lakh and upto 10 lakh</td>
<td>10%</td>
<td>25000/-</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Over 10 lakh and upto 25 lakh</td>
<td>8%</td>
<td>115000/-</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Above 25 lakh and upto 50 lakh</td>
<td>6%</td>
<td>235000/-</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Above 50 lakh and upto 75 lakh</td>
<td>4%</td>
<td>385000/-</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Over 75 lakh and upto 1 crore</td>
<td>2%</td>
<td>485000/-</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>More than 1 crore</td>
<td>1%</td>
<td>535000/-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

This notification shall remain effective upto 31.03.2021.

[No.F.7(47)/pari/rules/Hqrs/87/part-1/2]

By Order of the Governor,

(Mahendra Kumar Khinchi)
Joint Secretary to the Government

Government Central Press, Jaipur